हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 1979

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्रवार, 9 मार्च, 1979

पृश्ठ संख्या

सचिच द्वारा घोशणा	(8)1
तारांकित प्र न एव उत्तर	(8)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(8)23
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(8)28
ध्यानाकर्शण सूचनाएं– (i) राज्य के विभिन्न भागों मे ओलावृश्टि से हुई फसलों की तबाही संबंधी	(8)33
औचित्य प्र न	(8)36

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 9 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चंडीगढ़ मे प्रातः 9.30 बजे हुई। उपाध्यक्ष (कंवर विजय पाल सिंह) ने अध्यक्षता की।

सदस्यों द्वारा भापथ या प्रतिज्ञान

सचिवः मुझे सदन को यह सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय किसी आव यक कारण से आज हाजिर नही हुए है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय चेयर पर बैंठेंगे।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री उपाध्यक्षः साहेबान, अब सवाल होंगे।

Declaring of Jhajjar Constituency as industrially backward

***1065. Captain mange Ram:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Jhajjar Assembly Constituency as an industrially backward area; and

(b)if reply to part (a) above be in the affirmative the time by which the said proposal is likely to be materialized?

उद्योग मंत्री (डार. मंगल सैन):

(क) तथा (ख): झज्जर तहसील के उद्योगित पिछड़ा क्षेत्र घोशित करने के मामले पर विचार किया गया था और भारत सरकार को भी विचारार्थ भेजा गया था लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। परन्तु झज्जर तहसील की नाहड़ सब तहसील को राज्य सरकार द्वारा पहले ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोशित किया हुआ है।

कैप्टन मांगे रामः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल स्वामी आदित्यवे ा के रैजोल्यू ान के समय भी निवेदन किया था कि झज्जर को इंउस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया करार दिया जाये तो क्या मिनिस्टर महोदय झज्जर के इलाके को कल वाले रैजोल्यू ान मे इनकलूड कर लेंगे?

डाक्टर मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने कल भी निवेदन किया था कि झज्जर को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करार देने के लिये गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखा था परन्तु गवर्नमैंट आफ इंडिया ने माना नही। झज्जर की सब तहसील नाहड़ को पहले ही बैकवर्ड करार दिया हुआ है।

चौधरी राम कि ानः डिप्टी स्पीकर साहब? मैंने कल भी गुजारि ा की थी और मैंने सवाल भी किया था कि जिला जींद के

एरिया को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करार दिया हुआ है परन्तु सफीदों के एरिया को बैकवर्ड डिकलेयर नही किया हुआ जबकि वह बाढ़ग्रस्त एरिया है। क्या मिनिस्टर महोदय सैंट्रल गवर्नमैंट को अप्रोच करके सफीदों के इलाके को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया डिकलेयर करवायेंगे ?

डाक्टर मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, इनका प्र न भी आया था और वे इस बारे मे मेने से मिले भी थे कि सफीदों का इलाका बाढ़ के कारण पिछड़ा हुआ है। इनकी यह बात ठीक है और यह भी सत्य है कि जिला जींद के तीन ब्लाकों को बैकवर्ड डिकलेयर किया हुआ है लेकिन इनके एरिया को बैकवर्ड डिकलेयर नही किया हुआ। हम इनके इलाके के लिये भी प्रयत्न करेंगे कि इसको भी बैकवर्ड एरिया करार दिया जाये।

कंवर राम पाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हाउस मे बताया है कि झज्जर के इलाके को बैकवर्ड कडकलेयर करने के लिये सैंट्रल गवर्नमैंट को लिखा था परन्तु उन्होंने नही किया। तो मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसवजह से तो इंकार नही कर दिया कि जो भार्ते उन्होंने रखी हुई है उनको एरिया इन्होंने पूरा करके न भेजे हो ?

डाक्टर मंगल सैनः क्यों अस्वीकार किया इसके लिये तो नोटिस चाहिए। हमने तो अपनी तरफ से केस बना कर भेजा था परंतु जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था कि प्लानिंग

कमी ान के मैंबर श्री निवासन की अध्यक्षता मे ऐ कमेटी बनी हुई है। वह सारे ऐसे एरियाज के विशय मे विचार कर रही है कि किस एरिया को बैकवर्ड डिकलेयर करना चाहिये।

चौधरी लाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि नारायणगढ़ एरिया तो उन्होंने बैकवर्ड करार दे दिया है। परन्तु क्या उसका इन्डस्ट्री लगाने के लिहाज से भी ख्याल रखेंगे ?

डाक्टर मंगल सैनः इन्होंने स्वयं सवाल का जवाब दे दिया कि स्टेट लेवल पर बैकवर्ड डिकलेयर किया हुआ है।

चौधरी ई वर सिंहः मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोशित करने का क्या क्राइटेरिया है ?

डाक्टर मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, केंन्द्रीय सरकार से इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया करार देने के निम्नखिलित नार्मज है–

(1) जिस जिले को बैकवर्ड डिकलेयर करवाना हो तो वह लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजैक्ट से पचास मील दूर होना चाहिए।

(2) उस क्षेत्र की पर कैपिटा इंकम स्टेट की इंकम से 25 परसैंट कम होनी चाहिए।

(3) उस क्षेत्र मे उम्पलायमैंट की अपरच्यूनिटी कम हो।

(4) उस क्षेत्र मे कारखाने बहुत कम लगे हुए हो।

(5) उसमे यह भी ध्यान रखा जाता है कि उस क्षेत्र मे लोग प्राकुतिक साधनों का पूरा उपयोग न कर पाये हो।

(6) उस क्षेत्र मे बिजली है या अभी एक दो वर्शो मे बिजली आ जायेगी, इसी प्रकार पानी उपलब्ध है या एक दो वर्शो तक उपलब्ध हो जायेगा।

इस तरह से इन सारी बातों को ध्यान मे रखते हुए केंद्रीय सरकार ने नार्म फिक्स किया हुआ है। जहां तक राजय सरकार की ओर से नार्म फिक्स करने की बात है, हमारे से पहली सरकार ने कोई नार्म नही बनाया था। वे कैसे उन इलाकों को बैकवर्ड घोशित कर गये यह, कुछ नही पता लग रहा है। मैंने और सैक्रेटेरियट के लोगों ने फाइलें तला ा की परन्तु कोई ऐसी फाइल नही मिली। फिर भी मैं सदन को आ वासन देना चाहता हूं कि स्टेट लैवल पर बैकवर्ड डिकलेयर करने का नार्म तैयार कर लेंगे।

श्री सुमेर चंद भट्टः डिप्टी स्पीकर साहब, यहां हाउस मे बार बार मुखतालिफ इलाकों से यह मांग आ रही है कि हमारे इलाके को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिकलेयर किया जाये। इससे तो ऐसा लगता है बाकी स्टेट के इलाके तो इन्डस्ट्रीयली बहुत फार्वर्ड है। क्या उद्योग मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि सारी स्टेट के इलाकों के बारे मे एक बार ही विचार कर लिया जाये और

फैसला कर लिया जाये कि फलां फलां इलाके इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड है क्योंकि जब हमारा फैसला है कि सारी स्टेट को इंडस्ट्रीयली डिवैल्प करना है तो जो सुविधाये एक इलाके को दे रखी है वही सुविधायें दूसरे इलाकों को भी दी जायें।

डाक्टर मंगल सैनः मैं माननीय सदस्य की राय से इत्तफाक करता हूं कि बार बार यह मांग आती है कि हमारे क्षेत्र को बैकवर्ड एरिया डिकलेयर किया जाये क्योंकि वहां पर विकास नही हो पाया है। यह उनकी बात सत्य है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोगो को राजी करने के लिये पहली सरकार विमज मे आ कर कुछ इलाके बैकवर्ड डिकलेयर करती रही। अब हम सारी स्टेट के बारे मे पुनर्विचार के बारे में बैकवर्ड एरिया डिकलेयर करने का नार्म बनायेंगे।

चौधरी ि ाव राम वर्माः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसे कि जिले की तहसील या सब तहसील को बैकवर्ड करार देने के बारे मे विचार करते रहे है, वे एक बार ही सब कांस्टीच्यूएंसीज का आर्डर क्यों नही कर देते कि कौन कौन से क्षेत्र पिछड़े हुए है ?

डाक्टर मंगल सैनः मैंने यही तो निवेदन किया है कि हम सारे प्रदे ा की स्थिति पर विचार करके एक ही बाद बैकवर्ड डिकलेयर करना चाहते है।

श्री भागी रामः क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि इंउस्ट्रियली कौन सा क्षेत्र सब से पिछड़ा हुआ है?

डाक्टर मंगल सैनः इस सप्लीमैंटरी का मूल प्र न से कोई संबंध नही है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन ब्लाकों को सैंट्रल गवर्नमट के क्रइटेरिया के तहत पहले ही बैकवर्ड डिकलेयर किया हुआ हे और उनमे जो नोटिफाइड एरिया कमेटीज है जिनकी आजादी छः और सात हजार से ज्यादा नही है वहां पर सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं प्रदान नही की जाती है लेकिन दूसरी तरफ रूरल इंउस्ट्रिलाईजे ान के तहत जिन गांवों की आबादी छः सात हजार के करीब है वहां सरकार की तरफ से जब सुविधाएं प्रदानल की जायेग तो क्या इसी प्रकार से उन नोटिफाइड एरिया कमेटीज को भी वही सुविधायें जुटायी जायेगी जैसे उन गांवों को जुटाई जायेंगी?

डाक्टर मंगल सैनः मेरे आदरणीय सदस्य कुछ थोड़े से कन्फ्यूजड है। केन्द्रीय सरकार की ओर से उचाना और जो क्षेत्र पिछड़े हुए घोशित किये हुए है चाहे वे गांव है या नोटिफाइड एरिया कमेटीज है सब जगह इंडस्ट्री लगाने के लिये 15 परसैंट सबसिडी मिलती है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः नोटिफाइड एरिया कमेटियां उसमे नही है।

डाक्टर मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, इनकी जानकारी मे कमी है, हम सब सुविधायें देते है।

सरदार तारा सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि गुहला तहसील जोकि पंजाब के साथ लगती है और पंजाब के साथ वाले गांवों मे बहुत ज्यादा तरक्की हुई है लेकिन पिछली सरकार की मेहरबानी की वजह से हमारे यहां तरक्की नही हुई, क्या उसे भी इंडस्ट्रीयली पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोशित ? (ाोर)

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे मित्र सरदार तारा सिंह ने यह प्र न किया है कि गुहला तहसील के पड़ोस मे पंजाब के गांव विकसित हो गये है, क्या उनके एरिया को भी विकसित करने के लिये उसे इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिकलेयर करेंगे। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हम इसी महीने की 15 तारीख से ग्रामोद्योग विकास योजना आरम्भ करने जा रहे है। उसमे आप लोगों को लाइयेगा। जहां तक उस एरिया का इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करने का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया है कि जब सारे एरियाज पर विचार किया जायेगा तो उसमे गुहला भी स्वयं ही आ जायेगा।

श्री मूल चंद मंगलाः मंत्री महोदय ने हाउस मे कई बार फरमाया है कि हम गांवों मे इंडस्ट्रीज लगायेंगे। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जैसे एस्कोर्ट है,

क्या ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से खरीदे या बनवाए। मैं मंत्री महोदय से यह इसलिये जानना चाहता हूं क्योंकि छोटे छोटे जो पुजें गांवों की इंडस्ट्रीज मे बनेंगे वे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मे बड़ी आसानी करेंगे कि वे छोटे छोटे पुजें गांवों की इंडस्ट्रीज मे ही बनवाएं ?

डाक्टर मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब कल जब यहां पर एक प्रस्ताव का उत्तर मे यह कहा था कि हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजे ान की एक स्कीम या कम्पेन चला रहे है जिसका उद्घाटन 15 तारीख को मुख्य मंत्री महोदय ने करना है। उसमे सारे मंत्रिगण और सारे सदस्यगण भाामिल हों। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा था कि हम बड़े मंत्रिगण और सारे सदस्यगण भाामिल हो। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा था कि हम बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर यह भी कहेंगे कि वे एक एक उद्योग चाहे 5 लाख का या 10 लाख का गांवों मे भी लगाये। जहां तक माननीय सदस्य के इस प्र ान का ताल्लुक है कि हम उन्हे यह कहे कि वे छोटे छोटे पुर्जे हमारे गांव की इंडस्ट्रीज से बने हुए इस्तेमाल करे, हम उन्हे यह भी कहेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा जींद ब्लाक इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिकलेयर किया हुआर है लेकिन अभी तक वहां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर भी कोई भी इंडस्ट्री क्यों नही लगी है जबकि उसको इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिकलेयर किया हुआ है ?

डाक्टर मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, सदस्यों मे उत्सुकता और बैचेनी स्वाभाविक है क्योंकि उद्योग लगने से ही किसी क्षेत्र का विकास हो पाता है। मैं माननीय सदस्य कारे यह बता देना चाहता हूं कि वहां पर सरकार ने उद्योग नही लगाने है बल्कि इंटरप्रैन्योर्ज ने लगाने है। जींद जिले मे भालोट के मेहरबानो का एक कारखाना लगा हुआ है उसका तो इस्तेमाल कीजिये। (व्यवधान व भाोर)

Sports Stadium at Rohtak

***1015. Shri Jain Narain:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Sports Stadium at Rohtak, if so, the time by which the Stadium is likely to be constructed?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य): हां, रोहतक के खेल स्टेडियम के निर्माण कार्यो मे सहायता हेतु मामला सरकार के विचारधीन है। स्टेडियमज का निर्माण जिला स्टेडियमज कमेटीजो द्वारा खेल विभाग, भारत सरकार, ि ाक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये आि ांक अनुदान तथा स्थानीय रूपस से एकत्रित फंडज से किया जाता है।

यह आ ाा की जाती है कि जिला स्टेडियम कमेटी दो साल मे यदि पर्याप्त मात्रा मे फंडज जुटा सके तो स्टेडियम का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लेगी।

डाक्टर बृज मोहन गुप्ताः क्या मंत्री महोदय सह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा मे कितने स्टेडियम बनाने का विचार है और क्या कोई स्टेडियम अम्बाला जिला मे नारायणगढ़ या कालका मे बनाने का भी विचार है?

श्री हीरा नंद आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, ज्यो ज्यों धन की उपलब्धि होती जायेगी, हम सभी जिला हैडक्वार्टरस पर और दूसरे स्थानो पर भी स्टेडियम बनाते चले जायेगे?

श्री जगननाथः ि ाक्षा मंत्री जो भिवानी को विलांग करते है, उनसे मैं यह जानना चाहता हूं कि भिवानी जिला हैडक्वार्टर पर लगभग 15 लाख रूपये की लागत से एक स्टेडियम बनाने का प्रोपोजल है और 5–6 लाख रूपया उस पर खर्च हो चुका है लेकिन इतना रूपया खर्च करने के बाद भी वहां काम बंद पड़ा हुआ है। जो वहां पर घास लगायी गई थी, वहां अब गधे चर रहे है तो क्या उसे पूरा करने का प्रोपोजल है?

श्री हीरा नंद आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, यह बात इनकी बिल्कुल ठीक है लेकिन इसका पूरा होना धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इसलिये जब तक धन उपलघ नही होगा, इसे पूरा नही किया जा सकता है।

श्री जय नारायणः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा मे कुल कितने स्टेडियम है, और क्या रोहतक मे भी स्टेडियम बनाये जाने की प्रोपोजल विचाराधीन है ?

श्री उपाध्यक्षः इस प्र न का उत्तर तो मूल प्र न के उत्तर मे पहले ही दिया हुआ है कि वहां स्टेडियम के निर्माण कार्यो मे सहायता हेतु मामला सरकार मे भी कोई स्टेडियम बनाये जाने की प्रोपोजल विचाराधीन है ?

चोधरी उदय सिंह दलालः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े गांव हे और जहां के लड़के सारी दुनिया मे नाम रो ान कर रहे है, क्योंकि वहां पर सौ सौ लड़के कु ितयां करने वाले और दूसरे खेल खेलने वाले है ?

श्री हीरा नंद आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो इसका मूल प्र न से कोई संबंध नही है लेकिन फिर भी मैं उन्हे यह बता देना चाहता हूं कि हम मानोठी मे जरूर प्रबंध करेंगे।

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ि ाक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रोहतक के अंदर एक स्टेडियम तो सरकार बानो लग रही है और एक दूसरा स्टेडियम वहां पर वै य कालेज के अंदर बनाने लग रहे है जिसके लिये पिछले दिनों मुख्य मंत्री महोदय 10 लाख रूपये देने का एलान भी

करके आये हैं क्या मंत्री जी यह समझते है कि रोहतक के अंदर दो बड़े स्टेडियम बनाने की योजना उचित है ?

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, अभी तक तो भाायद तक तो भाायद एक भी कम्पलीट नही हो पाया है।

चौधरी संत कंवरः यह तो कोई जवाब नही है कि कोई भी कम्पलीट नही हो पाया है। वहां पर वै य कालेज के अंदर जो स्टेडियम बन रहा है, वह काफी बन चुका है। वहां पर 10 लाख रूपये सरकार ने भी दिया है। अगर वहां पर ही 5–7 लाख रूपया और दे दिया जाये और उसे ही पूरा करवा लिया जाये तो मेरा विचार यह है कि आपको दूसरा बनाने की जरूरत नही पड़ेगी।

श्री हीरा नंद आर्यः 10 लाख नही दिया गया है सिर्फ 2 लाख रूपये दिया गया है।

चौधरी संत कंवरः मेरे सामने एलान किया गया था।

श्री हीरा नंद आर्यः वहां पर सिर्फ 2 लाख रूपया दिया गया है।

कंवर राम पाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने श्री जगन नाथ के सवाल के जवाब मे यह माना है कि भिवानी मे जो स्टेंडियम बन रहा है, वाहं पर 5–6 लाख रूपया खर्च हुआ पड़ा है। उन्होंने यह भी माना हे कि उसका काम अब बंद पड़ा है और वह धन की उपलब्धि पर ही भाुरू हो पायेगा। तो मैं मंत्री

महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां पर 5–6 लाख रूपया खर्च हो चुका हे, अगर उसे पूरा नही किया जाता तोक क्या वह वेस्ट नही चला जायेगा ? अगर वेस्ट जाना है तो फिर खर्च ही क्यों किया गया ? इस पैसे को जो वहां पर लगाया हुआ है, बचाने के लिये, उस स्टेडियम को कब तक पूरा करवा दिया जायेगा? इसके बारे मे मंत्री महोदय स्पश्ट जानकारी हमें दे।

श्री हीरा नंद आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो भिवानी स्टेडियम के बारे मे जो सप्लीमैंटरी है उसका इस सवाल से कोई संबंध नही है लेकिन फिर भी मैं बता देना हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, जो पैसा उसमे लगाया गया है वह बार विडोज का पांच लाख रूपया पिछली सरकार ने लगाया था और आगे रैड क्रास से पैसा लेकर बनाया जाना था। खेल विभाग की तरफ से उसमे पैसा नही लगाया गया है। हम इस बारे मे कोि ा ा करेंगे कि किसी प्रकार धन की उपलब्धि हो ओर उस पैसे को ठीक ढंग से लगाया जा सके। इसके लिये विचार किया जायेगा।

श्री दीप चंद भाटियाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद जहां से 35–40 परसैंट पैसा बजट मे आता है, वहां पर भी कोई स्टेडियम बनाया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्षः मंत्री महोदय ने बताया है कि हम सब जगह स्टेडियम बनायेंगे।

श्री हीरा नंद आर्य: भाटिया साहब, फरीदाबाद मे भी जरूर बनायेंगे, आप चिंता न करे।

चौधरी ई वर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि एक समिति का गठन किया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला कुरूक्षेत्र मे भी कोई समिति बनाई गई है और क्या वहां पर स्टेडियम बनाया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष: इसका उत्तर आ गया है।

Construction work on the Feeder from Kalanwali head to Bani Canal

***1107. Shri Mani Ram**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the progress, if any, made so far regarding the covnstruction work on the feeder from Kalanwali ehad to Bani Canal'

(b) the time by which the lining work on Chautala, Teja Khera and Asha Khera Canals, which was started during the last year is likely to be completed; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to undertake the lining work on the canals while they keep running?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) नही।

(ख) चुटाला, तेजा खेड़ा तथा आ ाा खेड़ा नहरों को पक्का करने का कार्य क्रम ाः हो जायेगा।

(ग) हां।

श्री मनी रामः डिप्टी स्पीकर साहब, चुटाला मे बंदी लगाकर माइनर बनाई जा रही है। क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे की बंदी न लगाकर बराबर मे माइनर निकाल कर उसको पक्का कर दिया जाये ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जी नही।

श्री भले रामः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर फ्लड आते है वहां पर नहरों को पक्का करने का सरकार का कोई विचार है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, लाइनिंग का जो कार्य भाुरू किया गया है उसमे लाइनिंग या नहरों को पक्का करने की प्रायरिटी इस विनाह पर दी जाती है–(1) उस इलाके का या उस जगह का पानी नमकीन हो, सैलाइन वाटर हो और नहर का पानी देने के प चात् भी सैलाइन हो (2) वाटर लौगिंग हो (3) वाटर लौंसिज ज्यादा हों और (4) कमांड को इम्प्रूव करना हो।

यह चार क्राईटेरिया फिक्स किये गये है और इस आधार पर लाइनिंग की प्रायरिटी फिक्स की जाती है।

Government High/Higher Secondary Schools

***1078. Chaudhri Gaya Lal:** Will the Minister for Education be pleased to state the number of Government High/Higher Secondary Schools for girls in districts Gurgaon together with the number of girls hostels attached with them at present?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य):

(1) उच्च विद्यालय

(2) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

(3) छात्रावास

चौधरी गया लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जिला गुड़गांव मे 13 उच्च विद्यालय, छः उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और केवल एक होस्टल बताया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो 19 उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ये सारे कस्बों मे है या कोई गांव मे भी है ?

श्री हीरा नंद आर्यः इस समय वह इंफरमे ान मेरे पास नही है। इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये।

चौधरी गया लालः डिप्टी स्पीकर साहब, जिला गुड़गांव इतना बड़ा जिला है कि वहां से 12 एम.एल.एज. चुनकर आते है और पापुले ान के हिसाब से भी बहुत बड़ा जिला है लेकिन वहां पर केवल 13 उच्च विद्यालय और छः उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और केवल एक छात्रावास है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस जिले मे लड़कियों के लिये हाई स्कूल और छात्रावास और बढ़ाने के बारे मे विचार किया जायेगा?

श्री हीरा नंद आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी जगह पर लड़कियों के स्कूल की आव यकता होगी और धन उपलब्ध होगा तो वहां पर स्कूल भी बनाया जायेगा और छात्रावास भी अनाया जायेगा।

चौधरी खुर ीद अहमदः इस बात को देखते हुए कि जिला गुड़गांव इतना बड़ा जिला है और वहां पर केवल लड़कियों के लिये 13 हाई स्कूल है। इस एजुके ान इम्बलैंस को दूर करने के लिये अगले साल जो स्कूलों की अपग्रेडिंग होगी उसमे जिला गुड़गांव को प्रेफरैंस देकर लड़कियां के कुछ जयादा स्कूल अपग्रेड किये जायेंगे ?

श्री हीरा नंद आर्यः अगर लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करने के लिये कहीं से कोई नोटिस मिलेगा तो जरूर प्रायरिटी दी जायेगी।

चौधरी पीर चंदः डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने रजिया के अंदर गर्ल्ज स्कूल खालने का एलान किया था। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1979 मे वहां पर कोई गर्ल्ज स्कूल खोलने का सरकार का विचार है?

श्री हीरा नंद आर्यः मैं समझता हूं कि इस सप्लीमैंटरी से मैन क्वै चन का कोई संबंध नही है। फिर भी अगर मुख्य मंत्री ने कोई ऐलान किया था तो उसका पालन किया जायेगा।

श्री भागी रामः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिरसा मे गर्ल्ज हाई स्कूल कितने है?

श्री उपाध्यक्षः इसके लिये अलग से नोटिस चाहिये।

स्वामी अदित्यवे ानः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि तीस साल की आजादी के बाद जिला गुड़गांव मे जहां पर महीलाओं की संख्या लगभग आठ लाख की है, इतने कम स्कूल क्यों खोले गये है ?

श्री हीरा नंद आर्यः मैं समझता हूं कि मूल प्र न से इस सप्लीमैंटरी का कोई संबंध स्कूल खोले जाते रहे है और स्कूल खोलना धन की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है।

श्री मूल चंद मंगलाः डिप्टी स्पीकर साहब, पलवल मे एक गर्ल्ज हायर सैकंडरी स्कूल है। वहां पर सात सौ विद्यार्थी है और पन्द्रह सैक ान है लेकिन वहां परी केवल पांच कमरे है। ि ाक्षा मंत्री महोदय ने कहा भी था कि हम इस स्कूल की बिल्डिंग बनाने की कोि ा ा करेंगे और हमने भी एक लाख रूपया देने का वादा किया था कि एक लाख रूपया हम देंगे.....

श्री उपाध्यक्षः मंगला साहब यह सैपरेट क्वै चन है।

कंवर राम पाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, जैसे पहले प्रोग्राम था कि अगर कहीं पर लोग स्कूल के लिये बिल्डिंग बनाकर दे दे तो वहां पर स्कूल खोल दिया जाता था। हमारी सरकार जो एजुके ान को बढ़ाने की कोि ा ा कर रही है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर कहीं देहात मे लोंग स्कूल की बिल्डिंग बनाकर दे दे तो क्या वहां पर स्कूल खोल दिया जायेगा ?

श्री हीरा नंद आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, स्कूल केवल बिल्डिंग के आधार पर नही खालें जाते है। स्कूल के लिये और भी भार्ते होती है जैसे विद्यार्थी.....

कंवर राम पाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अगर सारी भार्ते पूरी कर दी जाये तब क्या स्कूल खोल दिया जायेगा ?

श्री हीरा नंद आर्य: डिप्टी स्पीकर साहब, सारी भार्तो के पूरा होने के बाद भी बजट मे जितने पैसे का प्रोविजन होगा उसके हिसाब मे ही स्कूल खोले जायेगे।

Robbery Cases

***1087. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the district wise number of cases of robbery registred durining the period from 1-4-77 to 31-3-78 and 1-4-78 to 31-12-78 in the State?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

जिला	1—4—77 से 31—3—38	1—4—78 से 31—12—78
अम्बाला	7	5
कुरूक्षेत्र	10	1
करनाल	5	5
सोनीपत	4	14
रोहतक	7	10
हिसार	10	3
गुड़गांवा	10	2
भिवानी	4	3
नारनौल	3	6
जींद	4	10
सिरसा	1	—
जोड़	65	59

श्री फतेह चंद विजः डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब मे बताया है कि 1–4–77 से 31–3–78 तक रोबरी के 65 केसिज हुए और 1–4–78 से 31–12–78 तक 59 केसिज हुए। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने केस ट्रेस मुलजमान का चालान हुआ है और कितने अन ट्रेसेबल है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, 1–4–77 से 31–3–78 तक रोबरी के कुल केसिज 65 हुए है, उन मे से 48 केसिज मे चालान हो चुके है, 8 केसिज अन ट्रेसड है, 4 कंसिज कर दिये गये और 5 अभी अंडर इंवैस्टीगे ान है। 1–4–78 से 31–12–78 तक रोबरी के कुल केसिज 59 हुए है। उन मे 28 केसिज अनट्रेसड है, 2 अंडर ट्रायल है, 6 कैंसिल कर दिये गये है और 23 केसिज जेरे तफती ा है।

श्री जगन नाथः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इन डकैतियों को करने वाले दूसरे स्टेओं से आते है।

श्री फतेह चंद विजः उपाध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि बाहर से आकर यहां पर क्राईम करते हैं हरियाणा के साथ यू.पी. बार्डर लगता है और लोग यू.पी. से आकर यहां पर उाका और क्राईम करते हैं मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस बारे मे हरियाणा सरकार की यू.पी. सरकार से

कोई बातचीत हुई ताकि इन डकैतियों और क्राईमज की रोकथाम की जा सके ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, इन वारदातो की रोकथाम तो हतारी सरकार पूरी तरह से कर रही है लेकिन यू.पी. सरकार से तो हम तभी बात करें जबकि डाका डालने वाले यू.पी. सरकार से पूछ कर डाका डालते हो।

चौधरी ई वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे डकैतियों के केसिज मे जो आफिसर्ज इंक्वायरी मे लगाये जाते हे वे तीन तीन महीने के बाद बदल दिये जाते है ओर वह इंक्वायरी पूरी नही हो पाती है, क्या मंत्री महोदय इस बात का आ वासन दिलायेंगे कि ऐसी इंक्वायरियों के लिये जिस अफसर को नियुक्त किया जायेगा उसको बीच मे बदला नही जायेगा ताकि इंक्वायरी वगैरह का काम निश्पक्ष और जल्दी हो सके?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नही है। अगर कोई पर्टिकुलर केस आनरेबल मैंबर के नोटिस मे है तो वे हमारे नोटिस मे लायें, हम देख लेंगे।

चौधरी राजेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा देखने मे आया है कि हाईवेज रोबरी दिन व दिन बढ़ती जा रही है, क्या सरकार ने इस की रोकथाम के लिये कोई इंतजाम किया है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय सरकार की तरफ से इस के लिये कई इंतजाम किये गये है। रात को मोबाईल

पैट्रोलिंग होती है और बैरियर्ज सैट अप किये गये है। यह कहना ठीक नही कि रोबरीज की गिनती बढ़ती जा रही है। ये फिग्गर्ज फलक्चुएटिंग होती है, कभी घटती रहती है, तो कभी बढ़ती रहती है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जितने मुलजम पकड़े गये है, उन मे आदि मुलजम कितने है और इस काम की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या पग उठाये है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैंबर इस के लिये अलग से नोटिस दे तो बता दिया जायेगा ।

चौधरी पीर चंदः उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर बताया गया और मैं भी समझता हूं कि हरियाणा के अंदर काफी डकैतियां हुई है, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्अ करेंगे कि इन डकैतियो की रोकथाम के लिये सरकार कोई पुलिस का स्पे ान सैल बनाने का विचार रखती है ताकि इन डकैतियो की संख्या कम हो सके?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने काफी प्रिवैंटिव इकदामात उठाये हे ताकि इन डकैतियों की रोकथाम हो सके परंतु चौधरी पीर चंद जी पता नही किस स्पै ाल सैल की बात कर रहे है, मेरी समझ मे नही आया।

श्री उपाध्यक्षः मैं आनरेबल मैंबर को सुजैक्ट करूंगा कि वे मिनिस्टर साहब को अपना सुझाव अलग से लिख कर भेज दे।

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो रोबरीज की फिग्गर्ज दी है उन मे हाई वेज रोबरीज कितनी ह?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इस समय इसका विवरण मेरे पास नही है।

श्री मांगे राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने अपने रिटन रिप्लाई मे बताया है कि 1–4–77 सये 31–4–78 के दरमियान जीन्द मे 4 और 14–4–78 से 31–12–78 के बीच मे 10 रोबरी हुई है। जीन्द्र के साथ तो कोइ वार्डर का एरिया नही लगता तो फिर इस इलाके मे इतनी रोबरीज होने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, रोबरीज और डकैतियों का तो मेरे विचार मे कोई कारण नही दिया जा सकता।

श्री फतेह चंद विजः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि कई साथ लगती स्टेटों के लोग हमारे हरियाणा मे आकर डाका डालते है (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब? इतना भाोर हो रहा है, सवाल भी बड़ी मु कल से सुनाई देता है, इसलिये मेरी

आपके द्वारा आनरेबल मैंबर साहेबान से गुजारि ा है कि सवाल जवाब के वक्त जरा भाान्ति रखे। अगर सवाल सुनाई देगा तथी हम उसका जवाब दे पायेंगे।

श्री उपाध्यक्षः मैं भी अभी आनरेबल मैंबर साहेबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जरा भाांति से लोग आकर हरियाणा मे डाका डालते है तो कया सरकार ने इसको रोकथाम के लिये अपने लेवल पर, आई.जी. लैवल पर या एस.पीज. लैवल पर उन स्टेटों से कभी कोई मीटिंग की है ताकि दूसरी स्टेटों से आने वाले लोगों को इस डकैती या क्राईम वगैरह के काम से रोका जा सके?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इस प्रकार की मीटिंग तो दूसरी स्टेटों के साथ होती ही रहती है।

श्री भले रामः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अब तक जितनी चोरियां हुई है, जितने डाके पड़े है, उनमे कितनी नकदी थी और कितना दूसरा माल था जो चोरी हुआ ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मैंबर को इसके लिये अलग से नोटिस देना चाहिए।

Acquisition of land for extending the Power House at Farrukh Nagar

***1108. Chaudhri Narain Singh:** Will the Ministers for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to acquire land in Bhatshani in District Mohindergarh, Farrukh Nagar and Khor in District Gurgaon, Jatthah in District Mohindergarh and naru in District Gurgaon for extending the power house at Farrukhnagar;

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the names of the land owners whose land is proposed to be acquired and the names of persons with their residential adddress belonging to the Scheduled Castes amonhgst them; and

(c) whether the Govenrment is aware of the fact that the persons belonging to the Scheduled Castes referrred to in part (b) above own smal land holdings and will thus practically be rendered landless?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, इस सवाल का जवाब मैं अंग्रेजी मे दूंगा। (a) There is a proposal.....(भाोर)

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे हिन्दी अच्छी प्रकार से जानते है अतः वे अपना जवाब हिन्दी मे ही पढ़ें तो उचित रहेगा –(ाोर एवं व्यवधान)–

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्वामी जी, पहले सभी सवालों का जवाब मैंने हिन्दी मे ही दिया है –(ाोर)–

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको हिन्दी की कापी प्रोवाईड कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी, अगर आप प्रोवाईड कर सकते है तो आप समझ भी सकते है। –(ाोर एवं व्यवधान)–

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इसका हिन्दी वर्णन स्पश्अ प्रिंट नही हुआ है इसलिये मैं इस सवाल का जवाब अंग्रेजी मे पढ़ना चाहता हूं।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को हिन्दी मे ही जवाब पढ़ना चाहिये (ाोर)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा–

श्री उपाध्यक्षः इस बारे मे अध्यक्ष महोदय पहले ही रूलिंग दे चुके है। (ाोर) के अंदर यह प्रोवीजन है कि जो मंत्री हिन्दी मे बोले उसके साथ सदस्यों को उसका अंग्रजी मे मिलता रहता है तो क्या हमारी विधान सभा मे भी कोई ऐसा प्रबंध किया जायेगा?

(इस समय मंत्री महोदय सवाल का जवाब फिर पढ़ने के लिये खड़े हुए)

स्वामी आदित्यवे I: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना कंरूगा कि आप महोदय को कहे कि वे अपना जवाब हिन्दी मे ही पढ़े (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी मैंने आपकी बात सुन ली है, आप बैठ जाइये। महोदय दानों मे से किसी भाशा मे भी जवाब दे सकते है।

स्वामी आदित्यवे I: उपाध्यक्ष महोदय, हम इनको इस जवाब का हिन्दी मे करके दे सकते है (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी आप बैठिये, मंत्री जी को जवाब देने दे।

Shri Verender Singh:

(a) There is a proposal to acquire land at Farrukhnager in District Gurgaon for upgrading the existing 33 KV Sub station. There is no proposal at present for aquiring land either at Bhatshani or Jatthah in District Mohindergah or at Khor or Nanu in District Gurgaon.

(b) The names of land owners whose land is proposed to be acquired at Farrukhnagar ara (i) Shri naryain Singh, M.L.A. and (ii) Shri Hira Lal Saini. The former belongs to the Scheduled Castes and his address is: Farrukhnagar District Gurgaon.

(c) The total land holdings of Shri narain Singh are not known. However only a small portion i.e. around 3 % of his holding in Farrukhnagar is proposed to be acquired.

चौधरी नारायण सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, जिन हरिजनों की जमीन सरकार ले रही है उनके पास गुजारे लायक ही जमीन है और इसके अलावा उनके पास कोई और साधन नही है तो क्या सरकार उनकी जमीन छोड़ने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः सह सवाल चौधरी नारायण सिंह जी की तरफ से पूछा गया है और इन्ही की जमीन इसमे इन्वाल्वड है। रिकार्ड के मुताबिक इनके पास 38 कनाल कुछ मरले जमीन है और उसमे से सरकार केवल 3 प्रति ान यानी एक कनाल चार मरले जमीन एक्वायर कर रही है जोकि बहुत थोड़ी सी जमीन है इसलिये मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि वहां पर पावर हाउस बनने दे। यह जो जमीन एक्वायर की जा रही है। यह कोई बहुत ज्यादा जमीन नही है जिससे ये लैंडलैस हो जायेंगे। इसके अलावा इस जमीन का मुक्म्मल तौर पर कम्पनसे ान दिया जा रहा है।

वित्त मंत्री (श्री मूल चंद जैन): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक प्र न आपके सामने उठाना चाहता हूं कि अगर कोई एम.एल.ए. किसी बात मे इंट्रैस्टड हो तो वह उस बारे मे हाउस मे सवाल नही पूछ सकता। यह हमारे रूल्ज मे प्रोवाईडिड है इसलिये मैं

आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस डिस्क ान की आगे इजाजत नही होनी चाहिए।

चौधरी खुर ीद अहमदः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय जी से गुजारि ा करूंगा कि वे श्री नारायण सिंह को बुला कर अलग से बातचीत कर लें और इस वाल पर आगे सप्लीमैंट्रींज अलाउ न की जाये।

श्री उपाध्यक्षः यह ठीक रहेगा।

State Text book Sales Depots

***966. Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Minister for health be pleased to state—

(a) the number of Govennment buildings of the State Tex Book Sales Deports in the Haryana State;

(b) the yearly amount of rent paid to the owners of the buildings since the formation of the Haryana State;

(c) the year in which the buildings mentioned in part (a) above were got constructed by the Government and whether there is any scheme under consideration of the Governemnt to construct more building if, not, the reasons therefore; and

(d) whether the Printing and Stationery Departement had asked the Government to allocate the Budget

for the construction of more buildings if, not, the reasons therefore?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा):

(क) तीन।

(ख) सूची संलग्न।

(ग) 1. रोहतक 1967

हिसार 1970

करनाल 1972

2.हां जी।

(घ) हां जी।

Statement

Financial year		Rent Paid
1968-69	Rs.	4546.00
1969-70	Rs.	15760.65
1970-71	Rs.	27585.79
1971-72	Rs.	21588.88
1972-73	Rs.	16980.70
1973-74	Rs.	20608.50

1974-75	Rs.	24659.40
1975-76	Rs.	32581.54
1975-77	Rs.	39368.88
1977-78	Rs.	41076.00
1978-79 (till 31-12-78)	Rs.	34679.00
Total	Rs.	27943534

चौधरी संत कंवरः मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहत हूं कि इस बार जो बजट मे रूपया रखा गया है उस रूपये से कौन कौन से जिले मे डिपो खोलने की प्रोपोजल है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः हमारी 9 डिपोज खोलने की योजना थी उसके लिये हमने 49 लाख रूपये की एलोके ान के लिये लिखा गया था लेकिन 4.60 लाख रूपये की स्वीकृति मिली। इसमे से 1979–80 के अंदर हम केवल एक लाख रूपये खर्च कर सकते है और इससे अम्बाला मे जमीन खरीदी जायेगी।

चौधरी लाल सिंहः मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि नारायणगढ़ मे दो जगह पर बस अड्डे के लिये जमीन एक्वायर की गई है इसलिये वहां पर बस अड्डा बनना चाहिए। (हंसी और भाोर)

श्री उपाध्यक्षः यह बस अड्डो के बारे मे सवाल नही है।

श्री देवेन्द्र भार्मा: मैं मंत्री महोदया से पूछनाचाहता हूं कि कुरूक्षेत्र, हिसार और रोहतक यूनिवर्सिटिएं जहां पढ़ने वालो को किताबों की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्या वहां भी कोई डिपों खोलने का विचार है अगर कोई विचार नही है तो उसका क्या कारण है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, जो हमने 9 नये डिपोज खोलने है उनमे कुरूक्षेत्र का भी नाम है।

Lake in Tehsil Jhajjar

***1063. Captain Mange Ram:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that bhindawas Lake was constructed near Shahjahapur, Bilochpura, Kanwah, Khetawas etc. in tehsil Jhajjar, Distt. Rohtak;

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative, whether any demarcation of the said lake has been made so far, if not, the time by which the said demarcation is likely to be made; and

(c) whether the compensation to all the land owners whose lands were acquired for the construction of the said lake has been given; if not, the time by which it is likely to be given to them?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) नही। भााहजहांपुर, बिलोचपुरा, कनवाह, खेतावास आदि तहसील झज्जर जिला रोहतक के निकट भिंडावास झील संचयागार बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस झील का सीमांकल कर दिया गया है और भूमि ले ली गई है।

(ग) हां, केवल उन भू–स्वामियो को छोड़कर जो अदायगी लेने नही आए।

कैप्टन मांगे रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बतलाया है कि झील की डिमार्के ान कर दी गई है लेकिन मेरे इलाके मे 8 गांव अभी भी ऐसे है जो पानी के नीचे आते है। उन गांवों मे अभी तक कुछ आदमियों को मुआवजा या कम्पनसे ान नही मिला हैं जब सरकार से पूछा गया तो यह जवाब दिया गया कि जो लोग मुआवजा लेने आये थे उनको दे दिया गया है। मै आपको बताना चाहता हूं कि वहां के कई इलाको के लोग पिछले दो साल से पानी से घिरे हुए है, उनके घर पनी से घिरे हुए है जिसके कारण वे लोग सरकार से पैसा लेने नही आये। तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन लोगो को मुआवजा दिया जाये और जो घर से बेघर हो गये है उनको कब तक रीहैबलीटेट करने का सरकार का विचार है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः कैप्टन मांगे राम जी आप मेरे साथ तारीख निि चत कर लें और उन आदमियों को ले आये, जिनको मुआवजा नही मिला है। उनको मुआवजा दे दिया जायेगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः क्या वजीर साहब, बतायेंगे कि किस किस तहसील मे लेक बनायी जायेगी और क्या उनमे कैथल का भी नाम है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः ऐसा कोई जवाब नही दिया जायेगा। इसके लिये अगर अलग सवाल पूछा जायेगा तो उस पर आप सप्लीमैंटरी पूछ सकते है।

चौधरी संत कंवरः यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि मुआवजा उन लोगों को दिया गया है जो स्वयं लेने गये है और जिन्होंने नही लिया है उनके लिये तारीख निि चत कर ली जाये तो उनको मुआवजा दे दिया जायेगा। क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन लोगो ने दूसरो की जमीन अपने पास रहन रखी हुई है वे भी मुआवजा ले कसते है ? उनको मुआवजा लेने के लिये कभी एल.ए.ओ. के पास जाना पड़ता है कभी कहीं जाना पड़ता है। उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिससे उन आदमी ने रहन ली है उससे लिखवाना पड़ता है। उन लोगो से लिखवाने के बावजूद भी उनको मुआवजा नही दिया गया। क्या सरकार इन लोगो को मुआवजा दिलाने के लिये कोई पग उठा रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मुआवजा हमे ाा असल मालिक को दिया जाता है जिसके पास जमीन रहन रखी हुई है उसको कभी भी नही दिया जातां अगर उसका मालिक स्वयं मुआवजा मांगं तो उसको मिलता है। अगर मेरे साथी को कोई इस बारे मे तकलीफ है तो वे लिख कर पूछे मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री भले रामः झील उस इलाके मे बनायी जाती हे जहां 5–5 या 7–7 सालो से पानी खड़ा रहता है क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि भंभेवा मे जहां 15 सालों से पानी खड़ा हुआ है वहां भी झील बनाने का कोई इंतजाम किया गया है, अगर हां, तो कब तक बना दी जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः चौधरी भले राम और राम कि ान जी अगर भंभेवा मे झील बनवाना चाहते है तो हम एग्जामिल करवायेंगे।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भिंडावास मे लेक बनाने के लिये कितनी जमीन एक्वायर की गई, प्रति एकड़ कितना मुआवजा दिया गया और मुआवजे की टोटल कितनी अमाउंट है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः टोटल अमाउंट बतौर मुआवजे के जो दी गई उसकी फिग्गर इस समय मेरे पास नही है। इसके लिये अलग नोटिस दे तो जवाब दे दिया जायेगा।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः मैंने तो तीन बातें पूछी है।

श्री उपाध्यक्षः आपको जवाब दे दिया जायेगा यदि आप अलग सवाल पूछेंगे।

चौधरी लाल सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी झीलें बनायी जाती है ये सिर्फ देखने के लिये या वहां प ाुओं को भी पानी पिलाया जा सकता है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः ये झीले पहली सरकार के समय देखने के लिये थी लेकिन अब यह सरकार इन झीलों को फलडिड एरिया मे बना रही है। इससे एक तो बाढ़ का पनी रोका जा सकेगा, दूसरे प ाुओ को भी आप पानी पिला सकते है। जहां खुद आदमियों को पीने का पानी नही मिलता उनको भी मिल सकेगा।

चौधरी देस राजः डिप्टी स्पीकर साहब, आगमैंटे ान कैनाल सन् 71 मे बनी थी लेकिन लोगो को आज तक कम्पनसे ान नही दिया गया जोकि 5 लाख रूपया बनता है। क्या मंत्री महोदय अगले तीन महीने मे लोगो को कम्पनसे ान दिलवा देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी दे ा राज जी आज मुझे मिल लें। अगर इसमे कोई कानूनी अड़चन न हुई तो तीन महीने से पहले ही दे देंगे।

Bridge on drai No. 8 near village Mrodhi

***1008. Shri Jai Narain:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal unde consideration Marodhi Kalan in district Rohtak?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): हां, गांव मारोदी कलां के निकट फुट ब्रिज विलेज ब्रिज मे परिवर्तित करने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

Life Sketches of the Saints

***1079. Chaudhri Gaya Lal:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give due place to the brief life skeches and preaching of the saints and greatement born in the downtrodden classes, in the language books to be taught to the students in the schools upto the 10th class; and

(b) if so, the time by which the aforsaid proposal is likely to be materialized?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य):

(क) हां।

(ख) आ ा की जाती है कि ऐसी अतिरिक्त पाठ्य सामग्री सहित पुस्तकें विद्यालयों मे वर्श 1980–81 के भौक्षिक स्तर से उपलब्ध कर दी जायेगी।

Shifting of Police Station

***1094. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether thee is any proposal under consideration of the Government shift the Police Station Urlana, district Karnal proposal is likely to be materialized?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): सरकार ने सिद्धांत रूप मे थाना उरलाना जिला करनाल को गांव मतलोडा मे ले जाना स्वीकार कर लिया है। उचित भवन उपलब्ध होने पर थाना को ि ाफ्ट किया जायेगा।

श्री फतेह चंद विज: जैसा कि आपने फरमाया है कि यह मान लिया गया है। 1912 से आज तक 67 साल हो गये है। आज पली फाईल देख ले पहले भी यहां थाना बनाने का फैसला किया गया था फिर सन् 1912 के बाद सन् 1918, 1920, और 1922 और 1922 मे भी फैसला किया गया था अब आप भी कहते है कि इसे मान लिया है। तो कब तक वहां थाना बना दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैंने तो अभी माना है अगले साल कुछ न कुछ प्रबंध करेंगे।

चौधरी लाल सिंहः अंग्रेजों के समय से रायपुर रानी के थाने की छत टूटी पड़ी है क्या उसको बनाने की सरकार की कोई प्रोपोजल है ?

श्री उपाध्यक्षः इस सवाल का इससे कोई संबंध नही है।

श्री देवेन्द्र भार्माः यह सवाल बड़ा अहम था यह होना चाहिये। जो पुलिस वाले सरकार की, लोगो की 24 घण्टे नौकरी करते है उनके बैठने के लिये खड़े होने के लिये जगह होनी चाहिये। आप जब उनसे 24 धण्टे काम लेना चाहते है तो अगर उनके बैठने के लिये जगह का इंतजाम ठीक तरह से न हो तो वे आपकी अच्छी तरह सेवा क्या करेंगे ?

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

Posts of P.As. in the Department of Controller of Printing and Stationery

***967. Chaudhri Sant Kanwa:** Will the Minister for Printing and Stationery be pleased to state—

(a) the number of posts of P.As. in the Department of the Controller, Printing and Stationery, Haryana, Chandigarh;

(b) the date on which the posts mentioned in part(a) above were sanctioned by the Government; and

(c) the names of emplyees who are working at present on the posts mentioned in part (a) above?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा):

(क) नियंत्रक, सुद्रण तथा लेखन सामग्री के विभाग मे निजी सहायक का कोई पद नही है।

(ख) और (ग) प्र न ही उत्पन्न नही होता।

Sagarpur Distributary

***911. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to extend further the tail of Sagarpur Distributary of Gugaon Canal; and

(b) if so, the details thereof, and whether it is likely to be extended up to Idhola?

Irrigation and Power Minister (Shri Virender Singh):

(a) There is no such distributary of Gurgaon Canal.

(b) In view of (a) above question does not arise.

स्वामी आदित्यवे I: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सीही गांव से जो माइनर कैनाल जाती है और आगे जाकर फिर सागरपुर के क्षेत्र से डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली गई है, क्या

इस डिस्ट्रीब्यूटरी को इधोला तक बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है?

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

श्री उपाध्यक्षः अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Report of the Committee appointed to enquire into the affairs of Private Colleges in the State

***1033. Shri Shamsher Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether Government propose to lay on the Table of the House the reprot of the Committee appointed to enquire into the affairs of Private College in the State'

(b) the names of the Colleges, the Committee recommended for taking over by the Government in the report: and

(c) the action taken by the Government on the report?

भिक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य):

(क) नही।

(ख) तथा (ग) इस स्टेज पर कालेजो का नाम बतलाना लोक हित मे नही है क्योंकि मामला अभी सरकार के विचारधीन है।

Criteria for upgrading Schools

***893. Chaudhri Jagdish Kumar beniwal:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the criteria if any, fixed by the Government for upgrading the Schools from Primary to Middle and Middle to High standard during the current financial year; and

(b) whether the Government has upgraded any school during the said period in the Darbha Kalan constituency of Sirsa District, if so, the names of such schools ans places where these have been upgraded?

िाक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य):

(ए) जी हां, स्कूलों का स्तर भूमि, भवन तथा छात्र संख्या पर निर्भर करता है।

(बी) जी हां, दड़बाकलां विधान सभा क्षेत्र मे निम्नलिखित स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया है:—

1978–79	प्राथमिक से माध्यमिक	माध्यमिक से उच्च
	राजकीय प्राथमिक पाठ ाला, मल्लिकां	राजकीय माध्यमिक पाठ ाला, मंगाला

Surprise Checking

***989. Shri Devender Sharma:** Will the Minister for Public Works be please to state—

(a) whether it is a fact that during recent surprise checks in various officers of the PWD B&R in Haryana sbout 10% staff was found absent/late; if so, the steps taken to check such indiscipline amongst members of th staff; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to re=organise the Development with a view to enforfed descipline?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लक्षमन सिंह):

(क) वर्श 1978–79 के दौरान लगभग 8 प्रति ात स्टाफ लेट अनुपस्थित पाया गया। दोशियों को चेतावनी दी जा चुकी है।

(ख) पुनर्गठित करने की कोई आव यकता नही समझी जाती है।

Shifting of Capital to Pai

***943. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:** Will the Chief Minister be please to state there is any proposal under consideration of the Government to shift the capital of Haryana from Chandigarh to Pai in Kuruksherra district; if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialized?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): जी नहीं।

Upgradation of Schools in Barwala Constituency

***970. Shri Jai Narain Verma:** Will the minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of schools upgraded from Primary to Middle and Middle to High Schools in the Barwala Constituency during the years 1977-78 and 1978-79 to date, separately; and

(b) the total number of Primary and Middle Schools which are proposal to be upgraded during the next financial year in Barwala Constituency?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य):

(ए) प्राथमिक से माध्यमिक माध्यमिक से उच्च

1977—78 भून्य भून्य

1978—79 एक भूल्य

(बी) अगले वित्तीय वर्श के दौरान राज्य मे 90 प्राथमिक स्कूलों और 90 ही माध्यमिक स्कूलों का स्तर ऊंचा करने का प्रस्ताव है।

Zonal and National Permits

***997. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Zonal and National Permits issued separately to private truck owners till 31-1-79 since the Janta Party Govt. started functioning;

(b) total number of Zonal and National Permits in Haryana which are likely to be issued upto 31-3-79; and

(c) the criteria adopted, if any, fro issuing the Permits mentioned in part (a) and (b) above?

Chief Minister (Chaudhri Devi lal): A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

	Number of Zonal/National Permits issued upto

(a)	**31-1-79.**		
	Zonal permits		National permits
	Western Zone permits	Northan Zone permits	
	4	2	100
(b)	**Number of Zonal/National Permits likely to be issued upto 31-3-79.**		
	Zonal permits		National permits
	Western Zone permits	Northan Zone permits	
	5	14	-

(c) Criteria adopted.

a(i) Zonal Schemes: The permits under Northern/Western Zone Schemes were sanctioned on the basis of models of vehicles. The new vehicles. The new vehicles were given preference to old ones.

(ii) National Permits:- The National permits wer3e granted in accordance with the criteria laid down by the Govt. of India originally as follows:-

(i) 50 % of the Nailanal permits wre granted to those who were already holding Inter State permits.

(ii) 25 % of the Permits to shose who were holding State/Regional permits.

(iii) 25 % of new enterpreneous including ex army personel and unemployed drivers.

The sanction of permits was, however, made on the basis of models of vehicles in each category referred to above.

(b) Zonal Nationa permits:- Sometime back the Govt. of India, left to the State Govts. to devise their own criteria. The State Govt., accordingly has now revised the criteria for grante of Zonal/National permits as under:-

(i)	Operators already in business	20 %
(iI)	New enterpreneurs from rural areas	15 %
(iii)	Un-employed drivers	10 %
(iv)	Ex servicemen	18 %
(v)	Scheduled Castes	15 %
(vi)	Backward Classes	2 %
(vii)	Persons victumised during Emergency and remained in Jails.	20 %

Removal from service of the employees of Cooperative Sugar Mills, Karnal

***1056. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will be the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state—

(a) the number of employees removed from service from the Cooperative Sugar Mills, Karnal during the period from 1-1-77 to 31-6-1978 togetherwith the number of persons employed during the said period; and

(b) the reasons for removal from service of the employees together with the method adopted for recruitment of new employees?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हटाए गए व्यक्तियो की संख्या			लगाए गए व्यक्तियो की संख्या		
नियमित	तदर्थ	कुल	नियमित	थोड़े समय के लिये तदर्थ आधार पर	कुल
23	18	41	40	41	81

(ख) मिल की सेवा से हटाए गए 23 नियमित कर्मचारियों मे से:–

(i) 6 व्यक्तियों की सेवाएं सक्रीनिंग कमेटी की सिफारि ा पर समाप्त की गई थीं क्योंकि ये भूतपूर्व सैनिक नही थे परन्तु भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों के वियद्ध कार्य कर रहे थे।

(ii) 2 व्यक्तियों की सक्रीनिंग कमेटी की सिफारि ाानुसार डिप्टी केन मैनेजर तथा मुख्य केन विकास अधिकारी कम केन के मैंनेजर के पदों की समाप्ति के कारण सेवा से हटाया गया था।

(iii) 4 व्यक्तियों को कार्य संतोशजनक ढंग से न करने के कारण हटाया गया था, तथा

(iv) भो ा 11 व्यक्तियों को लम्बे समय तक कार्य से गेर हाजिर रहने के कारण हटाया गया था

18 तदर्थ कर्मचारियो मे से 17 की उनकी नियुक्ति की अवधि के समाप्त होने के कारण तथा एक को दुर्व्यवहार के कारण सेवा से हटाया गया था।

जहां तक नए कर्मचारियों की नियुक्ति का प्र न है, उन्हे या तो रोजगार कार्यालयों के माध्यम से या अखबारों मे

ज्ञापन पत्र छपवाने के प चात् भर्ती किया गया था। निस्संदेह तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति प्रबंधक निदे ाक द्वारा स्वयं सीधे ही की गई थी।

अतांरांकित प्र न एवं उत्तर

Construction of Roads Constituency-wise

249. Shr Devi Dass: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the construction of all the roads sanctioned for each Assembly Constiuency during the year 1978-79 is likely to be completed upto 31-3-79; and

(b) the constituency wise names of the roads, if any, proposed to be constructed during the year 1979-80 together with the length of roads in each case?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लक्षमन सिंह):

(ए) नहीं जी।

(बी) वर्श 1979.80 के दौरान बनाई जाने वाली सड़कों के नाम व लम्बाई बताना सम्भव नही है परन्तु 2500 किलोमीटर की लम्बी सड़कें जो कि "State-wide programme" भाामिल है, मे से बहुत सी

सड़कें वर्श 1979.80 मे निर्माणाधीन होंगी और इस मे से 550 किलोमीटर की लम्बाई पूर्ण हो जायेगी।

Tax Stricture Review Committee

250. Shri Raghu Nath Goyal: Will the Minister for excise and Taxation be pleased to state—

(a) whether the Tax Structure Review Committee constituted by the Haryana Government has given its recommendations;

(b) if so, the action taken thereon?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(क) टैक्स स्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी ने अभी अपनी सिफारि ें देनी है।

(ख) प्र न उत्पन्न नही होता।

Abolition of Sales Tax

251. Shri Raghu Nath Goral: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish Sales Tax in the State, if so, the time by which it will be abolished?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह): जी नही।

Income accrued to the Haryana Roadways

256. Master Shiv Parshad: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total income accrued to the Haryana Roadways during the years 1977-78 and 1978-79 respectively alongwith the expenditure incurred on repair, tyre, tubes and spare parts dudring the said period; and

(b) the total profit earned or loss suffered by the Haryana Roadways during the years 1977-78 and 1978-79, separately?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

	लाख रूपयों मे	
	1977—78	1978—79
	अप्रैल, 78 से जनवरी, 79	
(क) कुल आय	3076.07	2740.89
खर्च		

(क) मुरम्मत और स्पेयर पार्टस पर टायर टयूब्ज	315.82	324.99
	226.61	323.87
(ख) हरियाणा रोड़वेज मे हुआ लाभ या हानि	54.23	(–) 4.54

Trips permitted on the Routes

257. Master Shiv Parshad: will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of routes of each Haryana Roadways Deport during tye years 1977-78 and 1978-79 alongwith the number of trips permitted on the each route; and

(b) whether the total number of trips permissible on each route were undertaken; if not, the details of the routes on which trips were not undertaken during each year together with the number of trips not undertaken in each case and the reasons therefor?

अंतरिम उत्तर

''अतारांकित प्र न 257 की सूची दिनांक 9.3.79 मे मास्टर ि ाव प्रसाद, एम.एल.ए. के नाम दर्ज विधान सभा अतांराकित प्र न संख्या का उत्तर अभी तैयार नही हुआ। ज्यों ही संबधित सूचना इकट्ठी हो जायेगी, अपेक्षित उत्तर भेज दिया जायेगा।

हस्ताक्षर

(देवी लाल)

मुख्य मंत्री

सचिव, हरियाणा विधान सभा,

चंडीगढ़।

अ ाः क्रमांग 10/42/79 परि0, दिनांक, चंडीगढ़ 9 मार्च, 1979''

Haryana Roadways Depots in the State

258. Maste Shiv Parshad: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the toral number of Haryana Roadways depots at present togetherwith the depotwise number and model of buses; and

(b) the deportwise nuber of new buses added during the years 1977-78, 1978-79 and the number of new proposed to be added during the year 1979-80?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): कथन I व II सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

कथन–I

इस समय हरियाणा राज्य परिवहन के 11 डिपों है। प्रत्येक डिपों की गाड़ियों की संख्या और माडल का ब्यौरा नीचे दिया गयाः–

	बसो के माडल									
डिपो	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	कुल
अम्बाला	15	28	47	13	37	88	–	24	14	266
गुड़गांवा	–	15	14	17	9	53	64	19	57	248
चण्डीगढ़	15	29	27	19	19	58	8	15	–	190
रोहतक	31	27	24	12	34	38	12	31	18	228
करनाल	15	35	46	15	17	53	7	29	–	217
हिसार	26	18	11	7	20	43	5	41	–	171

भिवानी	41	23	12	6	13	29	5	21	—	150
रिवाड़ी	16	4	29	19	25	31	8	6	17	155
जींद	—	11	35	35	10	34	15	20	—	173
कैथल	—	25	32	32	7	60	12	29	—	193
सिरसा	9	10	8	8	14	28	14	10	10	108
कुल	168	225	285	189	205	516	150	245	116	2099

कथन—II

(ख) प्रत्येक डिपो मे वर्श 1977—78, 1978—79 व 1979—80 मे नई बसें जो डाली गई उनका ब्यौराः—

डिपो	1977—78	1978—79	1979—80 (प्रस्तावित

	पुरानी गाड़ियो को बदलने हेतु	सेवाओं में वृद्धि हेतु	कुल वृद्धि	पुरानी गाड़ियो को बदलने हेतु	सेवाओं में वृद्धि हेतु	कुल वृद्धि	पुरानी गाड़ियो को बदलने हेतु	सेवाओं में वृद्धि हेतु	कुल वृद्धि
अम्बाला	12	12	24	31	25	56	11	69	37
गुड़गांवा	30	1	31	43	15	58	12	23	35
चण्डीगढ़	3	10	13	7	40	47	22	20	42
रोहतक	31	1	32	37	22	59	32	22	54
करनाल	15	14	29	—	6	6	20	20	40
हिसार	16	13	29	47	18	56	30	17	47
भिवानी	5	1	6	29	8	37	13	14	27

रिवाड़ी	8	11	19	—	—	—	2	15	17
जींद	11	2	13	21	10	31	38	14	52
कैथल	12	17	29	—	16	16	3	19	22
सिरसा	10	—	10	7	15	22	13	10	23
कुल	153	82	*235	222	175	397	196	200	396

*हरियाणा राज्य परिवहन ने वर्श 1977—78 के लगभग अंत मे 235 चैसिज खरीदी थीं लेकिन वास्तव मे यह बसें चालू वित्तीय वर्श मे मार्गों पर डाली गई क्योंकि पिछलें वर्श इन चैसिज पर बौडी नही बनाई जा सकी थी।

Grants to the Private Schools

259. Master Shiv Parshad: Will the Minister for Education be pleased to state whether the Govt. is considering any proposal to give grants to the private Schools on the pattern of private Colleges in aforsaid grants are likely to be given?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्य): जी हां, अभी तक कोई अंतिम निण्रय नही लिया गया है। इसलिये धन रा ि ा या तिथि जब से अनदान दिया जा सकेगा बताना सम्भव नही है।

ध्यानाकर्शण सुचनाएं–

(i) राज्य के विभिन्न भागों मे ओलावृश्ट से हुई फसलों की तबाही संबंधी।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सर्वश्री ि ा प्रसाद, भागमल, आदित्यवे ा, देवेन्द्र भार्मा, रामपाल सिंह, देसराज और ि ाव राम वर्मा, एम.एल.एज. से कुरूक्षेत्र जिले मे, गुड़गावां जिले की नूंह तथा पलवल तहसील के गांवों मे तथा जिला करनाल के गांवों मे दिनांक 4–3–79 से नूंह तथा पलवल तहसील के गांवों मे तथा जिला करनाल के गांवों मे दिनांक 4–3–79 से 7–3–79 तक ओलावृश्टि से फसल की तबाही के संबंध मे ध्यानाकर्शध प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते है। सर्वश्री ि ाव प्रसाद, भागमल, आदित्यवे ा, देवेन्द्र भार्मा, राम पाल सिंह,

देसराज और ि ाव राम वर्मा, एम.एल.एज. अपने प्रस्ताव पड़ दे। राजस्व मंत्री अगर चाहें तो वे अपना वक्तव्य दे सकते है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैन ान मो ान चार दिन से यहां पड़ा है लेकिन मुझे उस बारे मे कोई सूचना नही मिली। ये ध्यानाकर्शण प्रस्ताव कल दिये गये थे और आज आपने मंजूर भी कर लिये है (ाोर)।

श्री उपाध्यक्षः उसके बारे मे आपको लेटर जा चुका है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, उसके बारे मे मुझे कोई खत नही मिला। यह ध्यानाकर्शण प्रस्ताव कल आए है और मेरा एक हफ्ते से यहां पड़ा है।

श्री उपाध्यक्षः आपको सूचना दे दी गई है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बारे मे कोई सूचना प्राप्त नही हुई है (ाोर)।

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, एक ही सबजैक्ट पर चार चार काल अटैन ान मो ान जो है, बजाये इसके कि चार आदमी अलग अलग पढ़े, इसे एक ही आदमी पढ़ दे। बाद मे चारों का इकट्ठा ही मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे। (ाोर)

श्री मांगे राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब, कल हमारे जींद डिपो से जितनी बसें चली है वे सारी की सारी कोई 8 मील और कोई 10 मील चल करके रूक गई। इस बारे मे ड्राईवर्ज ने

जवाब दिया कि डीजल इतना खराब है कि कोई बस नही चल सकती। तो यहां हमारे चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब बैठे है क्या उनके नोटिस मे यह बात है ? मैं चाहूंगा कि इसकी इन्क्वायरी की जाये। जो हाई कोर्ट मे आने वाले लोग थे वे भी रह गये। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। क्या इसके बारे मे हमारे मंत्री जी रो ानी डालने की कृपा करेंगे?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, * * * * * * (ाोर)

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी जगजीत सिंह जी आप परमि ान के बगैर बोल रहे है, कृपया बैठिये। (ाोर) अब मास्टर ि ाव प्रसाद जी अपना ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पढ़ेंगे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी जगजीत सिंह पोहलू ने जो भाब्द कहे है उन्हें एक्सपंज किया जाये (ाोर) चौधरी जगजीत सिंह जी का रोज का यह काम है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्ष: जितना भी यह बगैर परमि ान के बोले है वह रिकार्ड मे नही आयेगा। (विघ्न एवं भाोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: देखिए, स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब की यह चेयर इतनी मान्यता के योग्य है और यह हर दफा इसकी मुखालफत करते हैं इसको मा ल के जरिये हाउस से फौरन बाहर करवाया जाये। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिये। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य चौधरी जगजीत सिंह पोहलू कई दिनों से अनमैनेजेबल होते जा रहे है और इस तरह से बीहेव करते है कि चेयर की तरवाह भी नही करते और इररैलेवैन्ट बोलते जाते है जबकि उस बात की रैलेवैंसी नही होती तो इनके खिलाफ कोई न कोई एक ान जरूर लिया जाना चाहिए। (ाोर)

राव बीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अपोजी ान मे चंद आदमी है तो क्या उनको इतना भी हक नही कि वे अपनी बात हाउस मे कह सके। अपोजी ान के आनरेबल मैंबर के लिये यह कहना कि अनमैंनेजेबल होते जा रहे है यह ठीक बात नही है। डिप्टी स्पीकर साहब, हम जानते है कि हाउस का डिस्पिलिन और डिगनिटी आपको कायम रखनी चाहिए। जहां तक डिस्पिलिन का संबंध है माननीय वजीर साहब पहले अपनी पार्टी को तो मैनेज कर ले (ाोर) हमारी अपनी तो हो जायेगी। यह आपस मे जिस तरीके से बिहेव करते है वह आपने देख लिया थार कि जब बजट पे ा हुआ था तब क्या हुआ था ? वह इनकी बड़ी मैनेजबल चीज थी, बड़ा अच्छा तमा ाा था। अगर दोनों तरफ से चेयर को सहयोग देने की बात हो तो हम भी मंजूर करते है। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: I would request the hon. Members to please maintain the decorum of the House.

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी एक काल अटैन ान मो ान थी.....

श्री उपाध्यक्षः प्रैजीडैंट साहब के अने की वजह से उस पर विचार नही हो सका, वह अंडर कंसिड्रे ान है।

***सर्वश्री ि ाव प्रसाद, भाग मलः** मैं अपकी आज्ञा से सदन का ध्यान अत्याव यक लोक महत्व के इस विशय की ओर दिलाना चहाता हूं अर्थात् हाल ही मे 5 मार्च, 1979 की औलावृश्टि के कारण जिला अम्बाला तथा कुरूक्षेत्र मे गेहूं, चले, सरसों तथा गन्ने इत्यादि की खड़ी विभिन्न फसलें बुरी तरह से नश्ट हो गई है और इससे कृशकों इत्यादि को बहुत भारी नुक्सान हुआ है। सारे इलाके/जिले मे फुट गहरे ओलों से ढक गए थे।

कृश्को/किसानों का आवयाना, भू–राजस्व, भूमि कर माफ किए जायें तथा उन्हें सरकारी एजैंसियों तथा सरकारी बैंकों के माध्यम से ऋण तथा सहायता भी दी जाये। उनहे रियायती दरों पर तकावी ऋण दिये जाये। ऋणो की वसूली एक वर्श के लिये स्थगित कर दी जायें जब तक पूरी हानि का पता न चल जाये उस समय तक यदि काई बिजली के बिल हो तो उनका भुगतान लम्बित रखा जाये। संबंधित मंत्री को कृपया इस अत्याव यक लोक महत्व के विशय मे वक्तव्य देने के लिये कहा जाये।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चहाता हूं कि

5–3–79 को ओलावृश्टि से नूंह, पलवल तथा बल्लभगढ़ और गुड़गांव तहसीलों के कई गांवों की फसलें नश्ट हो गई है। कृशि की फसलें जो कि किसानो तथा मजदूरों का आर्थिक आधार है इस असामयिक ओलावृश्टि से नश्ट हो गई है और इसके परिणाम स्वरूप किसानो का भविश्य अंधकारमय हो गया है.....(ाोर)

श्री भाम ोर सिंहः आन ए पवायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो रूल्ज आफ प्रोजीजर मे रूल है लेकिन जब सै ान भ्ाुरू हुआ था तो उस वक्त एक लैटर सरकुलेट किया था कि एक दिन मे सिर्फ एक काल अटैं ान मा ान एडिमिट की जायेगी लेकिन आपने आज चार काल अटैं ान मो ांज एडमिट कर ली है। क्या अपने रूल्ज को अमेंड कर लिया हे और वह सरकुलर वापिस ले लिया है ? क्या कारण हे कि आपने चार काल अटैं ान मो ान्ज एक ही दिल मे एडमिट कर ली है?

Mr. Speaker: Subject matter it the same.

Chaudhri Khurshid Ahmed: Though the subject matte ris the same but these cover differenct areas for the State. It is, therfore, very legitimate that all the members should read their motions separately.

राव बीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तरीके से काल अटैं ान मो ांज हाउस मे आ रही है और जिस तरीके से पढ़ी जाती है यह हाउस का प्रोसीजर नही है, काल अटैं ान मो ांज को हाउस मे लाने का कुछ अजीब

सा सिलसिला हो गया है। कायदा यह है कि काल अटैं ान मो ान का सब्जैक्ट ब्रीफली मैं ान किया जाता है और उस पर काल अटैन्ड ान मो ा रिजैक्ट करने के लिये वजुहात होंगी और उन वजुहात को अलग से दिया जाता हैं लेकिन जिस तरीके से काल अैटं ान मो ांज आ रही है और आपकी तरफ से इजाजत दी जा रही है, यह ठीक नही। एक लम्बे चौड़े नान आफि ियल बिजनैस को काल अटैन्ड ान मो ान बनाकर हाउस मे पे ा कर दिया जाता है और प्रस्ताव को पढ़ने का इजाजत आपकी तरफ से होती है। गवर्नमैंट को कुछ केहने के लिये गुंजाइ ा ही नही रहती। रीजन को, मैंटर आफ पब्लिक इम्पोर्टैंस के सब्जैक्ट को मैं ान करके गवर्नमैंट को जवाब देना चाहिए। मैंबर का एक्सप्लेने ान यहां नही पढ़ा जाता, यह गलत बात है । जिस तरीके से यहां पर प्रस्ताव पढ़े जाते हे, यह तरीका ठीक नही है, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

चौधरी रिजक रामः काल अटैं ान मो ान मे अलग वजुहात देने की आव यकता नही है। मैंबर के काल अटैं ान मो ान मे सबजैक्ट मैटर होता है, सब कुछ होता है, उसको मैंबर साहब ब्रीफली पढ़ दे। अगर सब को पढ़ना मुमकिन नही तो एक मैंबर पढ़ दे, क्योंकि सब के सब्जैक्ट मैंटर एक ही है। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंहः काल अटैं ान मो ान मे अरजैंसी बताने के लिये रीजन्ज दिऐ जाते है (व्यवधान)

Chaudhri Khrshid Ahmed: it is not necessary at all.

Rao Birender Singh: That is for the Chair to consider. You will kindly see that it is all in the from of a resolution.

श्री उपाध्यक्षः जो प्रोजीजर है उसके हिसाब से काल अटैं ान मो ांज एडमिट की जाती है और उसी हिसाब से पढ़ी जाती है। मैं रूल 73 की सब क्लाज (4) पढ़ देता हूं जो इस प्रकार है:—

"In the event of more than one matter being presented for the same day, priority shall be given to the matter which, in the opinion of the Speaker, is more urgent and important."

ओलावृश्टि के संबंध मे जो काल अटैं ान मो ांज आई है, वह एक ही सबजैक्ट पर थी, और इनको इम्पौर्टैंट समझ कर एक ट्रीट करके एडमिट किया गया । (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंहः मेरा सवाल यह नही है, यह तो चौधरी भाम ेर सिंह का प्वायंट आफ आर्डर था। मेरा प्वायंट आफ आर्डर दूसरा है और यह हे कि काल अटैं ान मो ान का जो फार्म है, बह बिल्कुल कायदे के खिलाफ है और ऐसी प्रैकिटस कभी नही रही.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मैंने सबमिट किया था कि सबजैक्ट मैटर सेम है। (व्यवधान)

राब बीरेन्द्र सिंहः कुछ ऐसी रिवायात कायम की जायें जिससे कायदा बिल्कुल न बदले।

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो काल अटैं ान मो ान एक पार्टिकुलर स्थान के लिये आते है, पार्टिकुलर जगह के लिये आते है, यह ढंग ठीक नही है। आप देख रहे है सारे हरियाणा मे ओलावृश्टि हुई है और हरियाणा के हर हिस्से मे बडी बेरहमी के साथ फसल बरबाद हुई। मैं आपका एक सैकिंड लेना चहाता हूं, और एक मिसाल देना चाहता हूं कि गोहाना के अंदर फसल तो बरबाद हुई ही है, इसके साथ प ाु भी मारे गये, जो नै ानल पक्षी है वे मारे गये, मनुश्य, भी मारे गये, मेरा कहने का मतलब यह है कि काल अटैं ान मो ान किसी पार्टिकुलर एरिए के लिये नही होना चाहिए क्योंकि सारे हरियाणा मे बरबादी हुई हैं गोहाना की सारी तहसली खत्म हो गई है और जिस तरह से ये काल अटैं ान मो ांज ला रहे है, इससे तो यह जाहिर होता है .....(ाोर)

Chaudhri Khurshid Ahmed: Is the making a speech or raising a point of order?

चौधरी गंगा रामः मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह मान कर आगे चलें कि किसी पार्टिकुलर एरिये मे नही बल्कि सारे

हरियाणा के अंदर फसल खराब हुई है और काल अटैन्शन मो ान सामूहिक तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

चौधरी गंगा रामः यह काल अटैं ान मो ान सामूहिक तौर से ट्रीट होनी चाहिए ताकि सारा हरियाणा इसमे आ जायें गोहाना तहसील बिल्कुल बरबाद हो गई है, प ाु मारे गये, मनु य मारे गये और नै ानल पक्षी भी मारे गये। (व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order. Please take your seat.

ध्यानाकर्शन सूचनाएं–

(i) राज्य के विभिन्न भागों मे ओलावृश्टि से हुई फसलों की तबाही संबंधी (पुनरारम्भ)

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पढ़ने के मध्य गतिरोध पैदा हो गया था, इसलिये मैं आपने प्रस्ताव को दोबारा पढ़ देता हूं:–

''मै सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चहाता हूं कि 5–3–1979 को ओलावृश्टि से नूंह, पलवल तथा बल्लभगढ़ और गुड़गांव तहसीलों के कई गांवो की फसले नश्ट हो गई है। कृशि की फसलें जोकि किसानो तथा मजदूरों का आर्थिक आधार है, इय असामयिक ओलावृश्टि से नश्ट हो गई है और इकसे परिणामस्वरूप किसानो का भविश्य अंधकारमय हो गया है।

इसलिये यह निवेदन है कि प्रभावित किसानो का राजस्व माफ किया जाये और उनके प ाुओं के लिये चारा जुटाया जाये और बैंको के कर्जो की वसूली स्थगित कर दी जाये। विद्यार्थियों की फीस भी माफ की जानी चाहिए।

यह क्षेत्र जो कि गत वर्श बाढ़ से तबाह हो गया था, ओलावृश्टि से और आधिक असहाय हो गया है।

इसलिये हरियाणा सरकार को प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिये ि ाघ्र पग उठाने चाहिए।''

चौधरी रिजक रामः वे भी जवाब देंगे, आप एक मिनट बैठिये।

श्री देवेन्द्र भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सदन का ध्यान अत्याव क लोक महत्व के इस विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में 5 मार्च 1979 को हुई ओलावृश्टि के कारण जिला तथा तहसील कुरूक्षेत्र के कौलापूरख ऊंटसाल, बांगडू, ई ारगढ़ मोरथला, मूसापूर करक माजरा तथा सूरजगढत्र इत्यादि गांवो की फसलें पूर्णतया नश्ट हो गई है।

इस क्षेत्र के कृशकों तथा मजदूरों की आर्थिक स्थिति पूर्णतया कृशि फसलों पर निर्भर करती है । इस क्षेत्र के कुशक लगातार पिछले दो वर्शे से बाढ़ों तथा ओलावृश्टि के कारण नुकसान उठा रहे है। सरकार से प्रार्थना है कि भू–राजस्व तथा बच्चों की कालेज/स्कूल की फीस माफ की जाये, बैंक के ऋणों की वसूली स्थगित की जाये और तकाबी के कर्ज माफ किये जाये। यह भी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के प्रथावित कृशकों को राहत दी जाये और उनके प ाुओं के लिये चारा इत्यादि भी जुटाया जाये।

सरकार से निवेदन है कि इस संबंध मे एक ब्यान दे और इस विशय मे भीघ्र पग उठाये।

***कंवर रामपाल सिंह, चौधरी देस राजः** मैं सदन का ध्यान अत्याव यक लोक महत्व के इस विशय की ओर दलाना चाहता हूं कि हाल ही मे 6 मार्च, 1979 को ओलावृश्टि के कारण जिला करनाल के लगभग 150 गांवो मे खड़ी फसलें जैसे कि गेहूं, चले, सरसो, गन्ना तथा अन्य विभिन्न फसलें पूर्णतया नश्ट हो गई है, जिसके कारण कृशकों को भारी हानि हुई है। सारा जिला ओलावृश्टि से ढक गया था, जिनका वजन लगभग 100 ग्राम से 500 ग्राम तक थां

कृशको/किसानों को आबयाने, भू–राजस्व, भूमिकर मे छूट दी जाये तथा उन्हे सरकारी अभिकरण, सरकारी बैंको तथा भूमिबंधक बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली एक वर्श के लिये स्थगित की जाये। बिजली के बिलों की अदायगी अगली फसल तक रोक दी जाये तथा प्रभावित किसानो को सहायता भी दी जाये। गन्ने की अदायगी तत्काल की जाये तथा प्रभावित क्षेत्र के गन्ने की अदायगी को पूर्वता के आधार पर देने के लिये आदे ा दिये जाये। प्रभावित किसानो को यह सहायता अविलम्ब दी जाये। संबंधित मंत्री को ऐसे लोक महत्व के मामले पर एक वक्तव्य देने के लिये कहा जाये।

चौधरी ि ाव राम वर्माः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान अत्याव यक लोक महत्व के इस विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि 4 मार्च, 1979 से 7 मार्च, 1979 तक जिला करनाल के सैंकड़ों गांवों मे ओलों की इतनी भरमार हुई कि किसानो की

फसल तबाह हो गई और करोड़ों रूपये का नुक्सान हो गया। गरीब किसानो के पास इतने साधन नही है कि वे उस नुक्सान को पूरा कर सके। इसलिये सरकार से यह निवेदन किया जाता है कि वह जिला करनाल के किसानो को उसी तरह से कंसै ान दे, जिस तरह से चंद रोज पहले सरकार ने दूसरे अन्य जिलों के लिये कंसैं ान देने के लिये इसी सदन मे आ वासन दिया था तथा इन गांवों मे से जिल गांवों मे पिछले वर्श भी ओलों से रबी की फसल नश्ट हो गई थी और उन्हें उसके बाद सरकार ने 100 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से तकाबी कर्जे दिए थे उनको इस ऋण से छूट देने की भी घोशणा की जाये।

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी हाल ही में एक बड़े खेद की बात हुई कि हरियाणा मे तकरीबन सब जिलों के अंदर ओलों से काफी नुक्सान हुआ है। (विघ्न)

औचित्य प्र न (पुनरारम्भ)

राव बीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। एक तो प्रैसिडैंट के खिलाफ एक काल अटैं ान मो ान की जगह पांच काल अटैं ान मो ांज एडमिट हुई है और पांचों का सबजैक्ट मैटर अलग अलग है और वे अलग अलग एरिया के कंसर्न रखती है। क्या मंत्री जी इन पांचों का अलग

जवाब देनें या इकट्ठा जवाब देंगे? अगर अलग अलग जवाब देंगे तब तो ठीक है वरना एक जवाब से ये पांचों कवर नही होती।

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार की ओर से सारी स्टेट के लिये जवाब आएगा जहां भी ओले पड़े है चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कोई एरिया हो सब को सहायता मिलेगी।

राव बीरेन्द्र सिंहः रूल बड़ा क्लीयर है कि एक दिन मे एक काल अटैन्शन मोशन से ज्यादा काल अटैंशन मोशंज हाउस मे नही आएगी लेकिन आपने पांच काल अटैंन्शन मोशंज पढ़ने की इजाजत दी है। क्या आपने यह रूल ससपैंड कर दिया है ? क्या ऐसा करने की आप को कोई खास पावर्ज है या आयंदा के लिये हाउस की सैंस लेकर के आपने यह प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि चाहे दस काल अटैंशन मोशन्ज हो या बीस काल अटैंशन मोशंज हो वे सब यहां पढ़ी जायेगी। यह जरा आयंदा के लिये क्लीयर कर दीजिए। आप कृपया रूल्ज के मुताबिक हाउस को चलाईये। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः स्पीकर साहब ने अपने आर्ड मे लिखा है कि–

"I am treating this as one Call Attention Notice as it pertains to commen subject"

Rao Birender Singh: Then only one man should be allowed. This is against the rule.

श्री उपाध्यक्षः हाउस मे ऐसी प्रैक्टिस नही है। (विघ्न)

राव बीरेन्द्र सिंहः यह प्रैक्टिस की बात नही है। रूल की बात है। जब आप प्रैक्टिस ही गलत डालते है तो रूल कहां रहेगा? (विघ्न) आप कह दीजिए कि स्ल को आप नही मानते।

श्री उपाध्यक्षः वह प्रैसिडैंट के बेसिज पर था।

राव बीरेन्द्र सिंहः क्या प्रेसिडैंट रूल को ओर राईट करेगा ? इसी पर आप अपनी रूलिंग दे दीजिये।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, देखने की बात तो यह है कि पांचों काल अटैं ान मो ान्ज का सबजैक्ट मैटर एक है।

श्री उपाध्यक्षः एक ही ट्रीट किया गया है और इम्पौर्टैंट समझ कर हाउस मे पढ़ने की इजाजत दी गई है।

राव बीरेन्द्र सिंहः इम्पौर्टैंट थी तभी तो ऐडमिट हुई लेकिन एक ही ऐउमिट हो सकती है, रूल यह कहता है।

श्री उपाध्यक्षः ऐसा प्रैसिडैंट की वजह से किया गया है, मेंने अपनी रूलिंग दे दी है।

राव बीरेन्द्र सिंहः आप मुझे एक बात बता दीजियें मान लो एक ही सबजैक्ट मैटर पर यदि 90 आदमी काल अटैं ान

मो ान दे दें तो क्या वे 90 की 90 काल अटैं ान मो ांज हाउस मे पढ़ी जायेगी? यह कौन सा रूल हुआ?

श्री देवेन्द्र भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि इस तरह से हाउस का टाईम वेस्ट नही होना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी अजीब सी बात है। हाउस के रूल्ज की तरफ यदि मैं तवज्जह दिलाऊं तो कहा जाये कि टाईम वेस्ट हो रहा है। इनको तो कोई फर्क नही पड़ता लेकिन मेरी गुजारि ा यह है कि रूल्ज के मुताबिक हाउस चलना चाहिए। (विघ्न) जिस तरीके से 5 काल अटैं ान मो ान्ज सैपरेटली हाउस मे पढ़ी गई है उसी तरीके से मंत्री महोदय को पांच उत्तर देने चाहिए।

Mr. Deputy Speaker: for answer, these will be treated as one, and only one answer will come. It is my ruling.

वक्तव्य–

(i) राजस्व मंत्री द्वारा राज्य के विभिन्न भागों मे ओलावृश्टि से हुई फसलों की तबाही संबंधी

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी हाल ही मे ओलावृश्टि से तकरीबन सारे हरियाणा के अंदर जो तबाही हुई हैं और सरकार ने इसके बारे मे सारे हरियाणा के लिये जो कदम उठाये है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

मास फरवरी तथा मार्च, 1979 मे राज्य के विभिन्न जिलों मे ओलावृश्टि से क्षेत्र मे बड़ी फसलों को बहुत हानि पहुंची है वि ोशतः अम्बाला, करनाल, कुरूक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांवा तथा सिरसा मे। सरकार ने प्रभावित किसानों को यथा संभव सहायता देने के लिये तुरंत कार्यवाही की है और ग्रैचुअस रिलीफ देने, बीज तथा खाद सबसीडी देने भूमिकर और आब्याना माफ करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा राहत के निम्नलिखित पगों की घोशणा की गई है:–

(क) ग्रैचुअस रिलीफ, सबसीडी तथा भूमिकर और आव्याना की माफी:

(1) ओलावृश्टि से खड़ी फसलों को पहुंची हानि से निम्नलिखित स्केल पर ग्रैचुअस रिलीफ दिया जायेगा:–

(i) खड़ी फसलों को 75 प्रति ात से अधिक हानि के लिये।	300 रूपये प्रति एकड़
(ii) जहां फसलों का नुक्सान 50 प्रति ात से ऊपर है, परन्तु 75 प्रति ात से अधिक नही है।	200 रूपये प्रति एकड
(iii) जहां खड़ी फसलों का नुक्सान 25 प्रति ात से अधिक है, परतु 50 प्रति ात से अधिक नही है।	100 रूपये प्रति

	एकड

(2) इसके अतिरिक्त कपास के लिये 40 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से बीज सबसीडी दी जायेगी। दूसरी फसलों के लिये जो इस अवधि मे बीजी जाती है, कृशि विभाग बीज खरीदकर उसे 50 प्रति ात तक सबसीडाईज करेगा।

(3) ओलावृश्टि से प्रभावित क्षेत्रों मे प ुओं के लिये चारा 15 रूपये प्रति क्विंटल के सबसीडाईजड दरों पर सप्लाई किया जायेगा।

(4) भूमिकर तथा आब्याना की वि ोश माफी उसी स्केल पर की जायेगी जिस पर वर्श 1979 की खरीफ फसल को बाढ़ों से हुई हानि के स्केल पर की गई थी।

(ग) तकावी कर्जे तथा दूसरी सहायताः

प्रति ात रियायती दर पर तकावी कर्जे निम्नलिखित ढंग से दिये जायेंगेः–

(i)	25 प्रति ात से कम हानि पर	भून्य
(ii)	25 प्रति ात से 50 प्रति ात तक की हानि पर	रू0 50 प्रति क्षतिग्रस्त

(iii) 50 प्रति ात से अधिक हानि पर	रू0 100 प्रति क्षतिग्रस्त

यह तकाबी बीज, खाद, चारा तथा ट्रैक्टर द्वारा का त के लिये दी जायेगी और यह उन प्रभावित क्षेत्रों मे सभी का तकारों को दी जायेगी–जैसे का तकार, मुजारे तथा हिस्सेदार इत्यादी।

(2) भूमि विकास बैंकों तथा कमि र्यल बैंकों को प्रभावित किसानो को दुधारू प ा खरीदने के लिये कर्जे उदारतापूर्वक से देने के लिये कहा जायेगा।

(3) जिन क्षेत्रों मे बढ़ावा 50 प्रति ान से ऊपर है, तकावी तथा और दूसरी प्रकार के कर्जे जिन मे सहकारिता कर्जे भी भाामिल है, वसूली 6 मास के लिये स्थगित कर दी जायेगी। सहकारिता विभाग को थोड़े समय के कर्जे मीडियम टर्म कर्जो मे बदली करने के लिये कहा जा रहा है।

(घ) उपरोक्त पगों के अतिरिक्त सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ओलावृश्टि से प्रभावित लोगो के बिजली के बिलों की वसूली जिनका नुक्सान 50 प्रति ात से ऊपर है, 6 मास के लिये स्थगित कर दी जायेगी।

फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत ओलावृश्टि से प्रभावित क्षेत्रों मे कार्य तेज करने का फैसला किया गया है ताकि लाभदायक रोजगार उपलब्ध हो सके। उपायुक्तों को ऐसे क्षेत्रों मे स्थानीय कार्य भ्रारू करने के लिये कह दिया गया है।

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो तीन सौ रूपये दिये जायेंगे, यह सबसीडी है या लोन है।

श्री प्रीत सिंहः तीन सौ रूपये रिलीफ के रूप मे दिये जायेंगे और जो तकावी है वह लोन के रूप मे दी जायेगी। तीन सौ रूपये वापिस नही लिये जायेंगे।

कंवर राम पाल सिंहः मिनिस्टर महोदय, ने अपने जवाब मे बताया है कि जहां पर 75 परसैंट खड़ी फसलों को नुक्सान हुआ है वहां पर 300 रूपये पर एकड़ के हिसाब से दिये जायेंगे। मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह परसैंटेज किस प्रकार से निकाली जायेगी क्योंकि फ्लड के टाईम पर जो परसैंटेज निकाली जाती है वह तो सारे गांव की निकाली जाती है क्योंकि फ्लड का पानी तो सारे एरिया को तबाह करता हूआ गुजरता है इसलिये सरी बीजी हुई फसल की परसैंटेज निकालते है। ओलावृश्टि तो किसी गांव के खास हिस्से से भी गुजर कर नुक्सान करती हुई जाती है और कुछ एरिया बच भी जाता है। अगर फ्लड की तरह से उनकी परसैंटेज निकाली गई तो जिन

लोगों के खेतों मे ओलावृश्टि हुई है उनको उतना पैसा नही मिल पायेगा। इसलिये आप यह साफ करें कि आया उन्हीं खेतों की परसैंटेज निकाली जायेगी जिन खेतों मे ओलावृश्टि हुई है या सारे गांव की परसैंटेज निकाली जायेगी।

श्री प्रीत सिंहः जिन किसानों के खेत तबाह हुए है, उनकी ही परसैंटेज निकाली जायेगी। (विघ्न)

औचित्य प्र न

श्री बलदेव तायलः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, काल अटैं ान मो ान पर मंत्री महोदय का वक्तव्य आ गया है क्या इस पर आप डिस्क ान अलाऊ करेंगे? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः इस पर सिर्फ दो प्र न कर सकते है और वे मैंने अलाऊ कर दिये है।

राव बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, एक काल अटैं ान मो ान पर दो दो प्र न अलाऊ करेंगे फिर तो आपको दस क्वै चन अलाऊ करने चाहिए।

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 73 की और दिलाना चाहती हूं। इसमे बहुत स्पैसिफिकली लिखा हुआ है कि there shall be no debate on

such statement at the time it is made. यह किताब अंग्रेजी मे है इसलिये मैंने अंग्रेजी मे पढ़ा है। इसको मैं हिन्दी मे भी बता रही हूं। रूल के तहत मंत्री महोदय का वक्तव्य आने के बाद इस पर चर्चा नही हो सकती। यह सवाल कैसे आया है कि इस पर डिस्कसन हो सकती है। यह हमारे नियम मे नही है।

Deputy Speaker: It is a new amendment.

श्रीमती सुशमा स्वराजः हमारे पास तो आई नही।

श्री उपाध्यक्षः डायरेक ान इ ू हो चुकी है। आपके पास भी पहूंच जायेगी।

Rao Birender Singh: A very importanct point has been raised by the Hon. Members but your ruling has not come.

श्री उपाध्यक्षः उस पर रूलिंग मैं पहले ही दे चुका हूं।

ध्यानाकर्शण सूचनाएं (पुनरारम्भ)

(ii) डी.एस.डी. कालेज, गुड़गांव के अध्यापकों द्वारा अनि ित काल तक क्रमिक भूख हड़ताल करने संबंधी

Mr. Speaker: I have recieved a notice of Call Attention Motion from Shrimati Sushma Swaraj, Chaudhri Khurshid Ahmed, Shrimati Shanti Devi and Swami Agnivesh M.L.As. concerning indefinite chain hunger strike by the

teachers of D.S.D. College Gurgaon. I have dissallowed it as according to Practice and Procedure by Kaul and Shakdher, page 406, Calling Attention notices on strickes, lock outs, fasts and agitation are disallowed in the Lok Sabha.

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है।

श्री उपाध्यक्षः मेरी रूलिंग पर प्वायंट आफ आर्डर नही हो सकता।

श्रीमती सुशमा स्वराजः मैं आपकी रूलिंग को चैलेंज नही कर रही हूं । एक रूल का सवाल है। आप मेरा प्वायंट आफ आर्डर सुन तो ले। मेरा व्यवस्था का प्र न यह है कि हरियाणा विधान सभा के नियम 73 के अंतर्गत किसी अरजेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले अलाऊ या डिस अलाऊ करेंगे या कौल एंड भाकधर की पुस्तक मे दी गई कन्वैं ांज के बेसिज पर।

Mr. Deputy Spaeker: We are following the practices & procedures of the parliament. Call Attendion nitices on strikes, lock outs fasts and agitation are not allowed.

श्रीमती सुशमा स्वराजः इतना पब्लिक इम्पोर्टेंस का सवाल है क्या आप उसको डिस अलाऊ कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्षः मैंने अपनी रूलिंग दे दी है। अब आप बैठिये।

वक्तव्य (पुनरारम्भ)

(ii) राजस्व मंत्री द्वारा टपरीवासियों तथा विमुक्त जातियों को अनुसूचित जन जातियों की सूची मे भाामिल करने संबंधी

Mr. Deputy Speaker: The Minister of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes had promised to make a statement in respect of *Call Attention Motion concerning the inclusion of Tapriwas and Vimukat Jatis in the list of Scheduled Tribes today. He may please do so.

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, इस काल अटैं ान का जवाब हिन्दी मे पढ़ने मे दिक्कत आयेगी क्योंकि हिन्दी का प्रिंट कलियल नही है। इसलिये मैं अंग्रेजी मे पढ़ देता हूं । (विघ्न)

Under the Criminal Trubes Act/(III) of 1911 enacted by Govt. of India, certain tribes were declared as Criminal Tribes.... (Interruptions)

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। मंत्री महोदय को हिन्दी मे जवाब पढ़ना चाहिए (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी, आप बैठिये। इसके बारे मे पहले ही रूलिंग दी जा चुकी है कि कोई भी मैंबर या मिनिस्टर जिस भाशा मे बोलना या पढ़ना चाहें पढ़ सकते है । दूसरे मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि इस को हिन्दी मे पढ़ने मे

कठिनाई आयेगी क्योंकि इसका प्रिंट ठीक नही है। इसलिये इसे अंग्रेजी मे पढ़ना चाहते है।

Shri Preet Singh: Under the Cirminal Tribes Act (III) of 1911 enacted by Govt. of India, certain cribes were declared as Criminal Tribes. On the basis of recommednations of a Committee appointed in 1913 by Punjab Govt. as separate Departement know as Criminal Tribes Departement was created some time in 1917 to run reformatory industrial and agriculture settlement for the memebrs of these ribes. The Criminal Tribes Act (III) of 1911 was later replaced by Criminal Trubes Act. 1924. With the dawn of independiance the law on this subject was repraled in 1952 and the casted listed as Criminal Tribes where lenotified.

2. In view of their economic and educational backwarkness, some of the Denotified Tribes (Vimukat Jatis) like Bengali, Barar, Bauria, Nut, Ghandila, Sansi (Manesh, Bhedkut) were included in the list of Scheduled Casts and other sub castes of Sansi like Kuchbadn, Rechband, Aheria, Heria, Singikat, Singiwala and Kanjar were declared by the State Govt. as Backward Classes. Some Denotified Tribes and sub castes of Sansi like Gadri, Kepat, Tettlu, Bherta, Arhar, Bhattu, Chattu, Habura, Kikan, Harrar, Mehla, Rehlnwala, Biddu, Length, Kalkhr, Mirshikar, Dhe, Bhagiarmar, Ghaddi or Ghadi, birtwan, Be-halia, Pakhiwara, Baddon Hami, Bhanttu, Harni, Tagus of Karnal District Dhinwara of Gurgaon District and Minas of Gurgaon District are neither included in the Scheduled Castes nor Backward Classes lists. They may deem to have been shown as advanced/upper castes. This information has been given int he enclosed annexure. Thus,

some of these communuties are enjoying in benefits available to the members of Scheduled Castes and Backward Classes respectively.

3. The approximate population of the Vimukat Jatis included in the Scheduled Castes is about fifty to seventy thousands computed from 1971 census. These Castes have not been able to identify themselves with the upper castes not with the Scheduled Castes in the State. The census record does not record separately facts about the backward classes communities like other advanced or upper castes. (At this stage Mr. Speaker occupied the Chair). Hence no population figures about the Vikumat Jatis listed as Backward Classes is availabe. So also there is no figure about the denotified Tribes or sub castes of Sansi who are not included either as Scheduled Cases or Backward Classes. (Interruptions)

Mr. Speaker: Order please. The Hon. Minister is making a astatement. I would request the Hon. Members to show due respect to him and listen to him patiently.

Shri Preet Singh: The statement further reads—

4. Before 1952 all these castes were treated as Criminal Trubes and not as Scheduled Tribes. In 1952 they were denotified from the list of Criminal Tribes and hence they are called as Denotified Tribes.

5. The purpose of the Call Attention Notice is that these people are socially, economically and politically backward and unrepresented in Govt. Sertvice. Under these circumstances the State Govt. may recommmednd to the Govt. of India that the whole list of Denotified Tribes (Vimukat jatis)

in Haryana State may be declared as Scheduled Tribes under article 342 of the Constitution of India. The State Government have already recommended to Government of India to declare them as Scheduled Tribes as has been done by Punjab.

6. After these castes have been declared as Scheduled Tribes by Govt. of India, other demands made by the Federation as set out in the Call Attention Notice would be sympathetically considered by the State Govt.

7. Meanwhile the Govt. will collect information about facts and figures though the District and Local Administration to assess the magnitude of the problems.

8. The Directorate of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classed will handle the problem till full information is obtained.

9. Govt. will sympathetically consider to include a member from the community in the Phul Chand Committee which was appointed to look into the grievances of Scheduled Castes and Backward Classes and the terms of reference would be extended to cover the denotified tribes also.

10. Govt. will sympathetically consider to include the representatives of these communities in District Grievances Committees,

11. During Indernational year of the Child, 1979 the State Govt. can assist any voluntary organisation who can set up Ashrams or Hostels for the education of their children.

12. Govt. will consider other economic problems sympathetically after Govt. of India accpet the proposals to include them in the list of Scheduled Tribes.

Annexure

List of Denotified Tribes

Scheduled Castes

1. Bengali
2. Barar
3. Bauria
4. Nat
5. Gandhila
6. Sansi(Bhedkut, Manesh)

Backward Classes (Sub-Caste of sansi included in Backward Classes)

1. Sansi.
   (i) Kuchband
   (ii) Rechhband
   (iii) Aheria, Heria
   (iv) Singiwala
   (v) Singkat

(vi) kanjar

General (not included in both the lists)

1. Sansi

(i) Gadri

(ii) Kepat

(iii) Tettlu

(iv) Bherta

(v) Bheria

(vi) Arhar

(vii) Bhattu

(viii) Chattu

(ix) Habura

(x) Kikan

(xi) Harrar

(xii) Mehla

(xiii) Rehlnwala

(xiv) Biddu

(xv) Lenglh

(xvi) Kalkhar

(xvii) Mirshikar

(xviii) Dhe

(xix) Bhagiarmar

(xx) Ganddi or Ghadi

(xxi) Birtwan

(xxii) Behalia

(xxiii) Pakhiwara

(xxiv) Baddon

(xxv) Hami,Bhanttu

(xxvi) Harni

2. Tagus of Karnal Distt.

3. Shinwara of Gurgaon Distt.

4. Minas of Gurgaon Distt.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह जो जवाब पढ़ा है, इसमे अगर वे मानें तो इस तरह की सिफारि ा क्यों न करें कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग है, उन्हें भी ि ाडयूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज की तरह से रिजर्वे ान दी जाये और उन्हें भी इस रिजर्वे ान मे भामिल कर लिया जाये ताकि उन लोगों को जो सहूलियात मिलती है, वे इन्हे भी मिल सकें और वे भी इन लोगो के बराबर आ सके।

श्री अध्यक्षः यह तो एक मुख्तलिफ सब्जैक्ट है क्योंकि यहां पर तो पिछड़ी हुई जातियों के बारे मे एक काल अटैं ान मो ान था। जो इकोनोमिकली बैकवर्ड लोग है, उसके बारे मे आप चाहते है तो यह विशय दूसरा हे। अगर आप नोटिस देंगे तो सरकार जरूर उस बात पर विचार करने की कोि ा ा करेगी।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा–

प्रिविलेज कमेटी की दूसरी प्रारम्भिक रिर्पोट पे ा करने को स्थगत करने संबंधी

Mr. Speaker: Hon. Members the nect item on the agenda relates to the presentation of the sercond Peliminary Report of the Committee of Privileges. But keeping in view the request of the Leader of the House and the amendment that I have also recieved, if I have the premission of the House, I want to defer this item to some subsequent day. (Voices; Yes) Thank you.

पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की पहली रिर्पोट पे ा करना

Mr. Speaker: Now, the Chairman, Committee on public Undertakings will rpesent the first Report of the Committee on Public Undertaking.

लाला बलवंत राय तायल (चेयरमैन, पब्लिक अंडटेकिंग्ज कमेटी): स्पीकर साहब, मैं हरियाणा माचिस लिमिटिड, बूरिया के सामान्य कार्यकरण पर सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति (1978–79) की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

वर्श 1978–79 के लिये अनुपूरक अनुमान (तीसरी कि त)

Mr. Speaker: Now the House will take up the Supplimentary Estimates (Third Instalment) for the year 1978-79.

(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

Mr. Speaker: Those hon. Memebrs who wish to discuss the charged items please do so.

(No member rose to speak.)

(ii) अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: According to the previous practice and to save the time of the House all the demands for grants appreaing on the Order Paper will be deemed tohave been read and moved. आनरेबल मैंबर्ज जिस विशय पर डिस्क ान रेज करना चाहे, कर सकते है लेकिन बोलते समय कृपया यह इंडीकेट करेंगे कि कौन सी डिमांड नम्बर पर वे डिस्क ान रेज करना चाहते है। Guillotine will be applied at 12.40 p.m.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 652350 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1097760 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.2-General Adminsitration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4976515 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4026550 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7293700 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.7-Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 53023000 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.8-Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25015400 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11642855 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.10-Medical and Public Helth.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 522814 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2749815 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4829420 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20250680 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17977930 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.21-Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 125893100 granted to the Governor to defray the changes that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.25-Loans and advances by State Govenrment.

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह जो अनुपूरक अनुमानो द्वारा मांगें पे ा की गयी है, इसमे से मैं मांग संख्या 1,2 और 4 के बारे मे अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। मैं इन डिमांडज के बारे मे अपने विचार बड़े संक्षिप्त रूप से ही रखूंगा। स्पीकर साहब, अपने विचार और तजरबे के आधारपर मैं एक बात महसूस करता हूं कि ये जो डिमांडज है, इन्हें सप्लीमैंट्री डिमांडज कहना उचित होगा। (व्यवधान) हमारा छोटा सा प्रांत है ओर इसमे तकरीबन सभी महकमों के लिये इन अनुपूरक अनुमानों द्वारा धन की मांग की गई है। इसमे दो बाते पैदा होती है जिन पर हमें विचार करना पड़ेगा। एक तो यह कि आर्थिक व्यवस्था के ऊपर सरकार का नियंत्रण नही है। सरकार का आर्थिक व्यवस्था के ऊपर वह कंट्रोल नही जो कि होना चाहिए वरना कभी भी सप्लीमैंट्री डिमांडज के द्वारा इतने भारी पैसे की मांग नही की जाती। इससे पहले भी दो बाद डिमांउज आ चुकी है और यह

तीसरी बार डिमांड आई है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार का जो फाईनैंि ायल कंट्रोल है, डिस्ट्रीब्यू ान, है, खर्च करने का जो तरीका है वह ठीक नही है। स्पीकर साहब, पिछली बार चौधरी सतबीर सिंह ने बजट पे ा किया था और उसके बाद भी जैन चौथे फाइनैंस मिनिस्टर है। एक साल मे चार फाइनैंस मिनिसटर बदल चुके हैं यह भी पता नही कि मुख्य मंत्री का श्री जैन के बारे मे आखिरी फैसला हे या नही। हो सकता है कि बजट सै ान मे ही कोई परिवर्तन हो जाये ओर यह कोई बड़ी बात नही है। आज तक किसी भी स्टेट मे ऐसा नही हुआ हे कि एक साल मे चार मिनिस्टर बदल जाये। स्पीकर साअब, ऐसी कोई बात नही है कि जो पहले मंत्री थे वे काबिल नही थे। वे सारे के सारे योग्य थे और यह भी ठीक नही है कि बजट के बारे मे जो उनकी प्लानिंग थी उसमे कोई कमी थी। लेकिन ऐसा लगबता है कि मुख्य मंत्री की मर्जी के मुताबिक खर्च की अनुमति जो मंत्री न दे, उसको चलता कर देते है या चौधरी वीरेन्द्र सिंह इतने ताकतवर है कि इनकी बात को न माना जाये तो भी चलता कर दिया जाता है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह की भाक्ति भी मुख्य मंत्री की भाक्ति से कम नही है। (व्यवधान)। स्पीकर साहब, मुझे खु ाी है कि मेरे मित्र भी सूबे मे नही है कि किसी मंत्री के पास इरीगे ान औरी पावर के साथ पुलिस की सारी भाक्ति हो (व्यवधान)। स्पीकर साहब, डिमांड नंबर एक मे कहा गया हे कि इस धन रा ि ा की इसलिये डिमांड रखी गई है कि मंत्रिमण्डल का विस्तार किया गया है। मत्रिमण्डल मे विस्तार भी किया गया ओर कुछ महकमों मे भी रोज रोज की

बदली की जाती है। स्पीकर साहब, जब से यह सरकार बनी है और आपका भी तजर्बा है कि आपको पहले दिन ि ाक्षा मंत्री की भापथ दिलाई गई फिर उल्टी ले ली और आपको स्पीकर बना दिया.....

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आपसे रिक्वैस्ट हे कि जो डिमांड हे उस पर ही बोले।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मैं डिमांड नंबर एक पर बोल रहा हूं। आपने ि ाक्षा मंत्री के पद पर बड़ी योग्यता से काम किया और आपने कोई पक्षपात नही किया और जिस वक्त आपको स्पीकर बनाने के बारै मे तजवीज थी उस वक्त हमारे यह प्रस्ताव रखा था कि आप ि ाक्षा मंत्री भी रहे और स्पीकर भी रहें लेकिन यह बात मानी नही गई। स्पीकर साहब, हालत तो यह है कि जब भाुरू मे सरकार बनने लगी तो एक दफा अखबारों मे आया कि स्वामी अग्निवे ा को मंत्रिमण्डल मे लिया जा रहा है। अगले दिन जब वह तैयार होकर आए तो इनका नाम साफ था। फिर कभी सुशमा जी का नाम आया, कभी कमला वर्मा जी का नाम आ गया और अब भी रोज अखबारों मे यह सूची जाती है कि फलां मैंबर को भामिल किया जा रहा है। रोज दो तीन नाम छपते है। कभी खुर ाीद का नाम और कभी सुशमा का नाम छपता है..... ....

श्री अध्यक्षः कृपया आप डिमांडज तक ही अपने को सीमित रखे।

चौधरी रिजक रामः मैं डिमांड नम्बर एक पर बोल रहा हूं। स्पीकर साहब, वह राज्य कभी भी ठीक नही चल सकता है जिसमे स्थिरता नही । अब तो हालत यह है कि आज एक महकमा एक मिनिस्टर को दिया जाता है और कल को उससे छीन लिया जाता है। आपके सामने इस चीजल की मिसालें है। कुछ दिन हुए चौधरी मेहर सिंह राठी को पी.डब्ल्यू.डी. का महकमा दिया गया लेकिन वह उनके मआफिक नही था क्योंकि वे सारी स्टेट को सड़कें देना चाहते थे और यह बात चौधरी वीरेन्द्र सिंह को पसंद नही थी इसलिये अगले ही दिन चौधरी राठी को जेल का ओर सांग का महकमा दे दिया...

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, हरियाणा मे सांग का कोई महकमा नही है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अंग्रेजी मे इस डिपार्टमैंट को कल्चरल डिपार्टमैंट कहते है और हिन्दी मे इसका अर्थ सांग होता है । हीरा नंद आर्य को पहले लेबर और अम्पलाएमेंट डिपार्टमैंट दिया। मजदूरों के साथ जो ज्यादती हो रही थी ये उसको दूर करना चाहते थे। लड़कों को रोजगार देना चाहते थे लेकिन वह विभाग श्री आर्य से वापिस ले लिया। डा. मंगल सैन के पास पहले पुलिस का विभाग था और ये कोि । ।

कर रहे थे कि कतल कम हो और डाके कम हो लेकिन इससे वह डिपार्टमैंट वापिस ले लिया और वीरेन्द्र सिंह को दे दिया । हमें कोई ऐतराज नही है चाहे किसी को दे। स्पीकर साहब, इस तरह की कितनी ही मिसालें है। स्पीकर साहब, इरीगे ान और पावर का डिपार्टमैंट खासा बड़ा है लेकिन इनकों तो अपनी सेहत बनाने का बड़ा फिक्र है और स्पीकर साहब, इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया था और आपको पता हे कि इस साल मे कत्ल भी ज्यादा हुए है, डाकों की तादाद मे भी बढ़ौतरी हुई है और चोरियां भी ज्यादा हुई है। स्पीकर साहब, ज्यादा न कहते हुए मेरा तो इतना ही कहना है कि मंत्रिमण्डल मे इस ढंग से छेड़छाड़ करना रोज परिर्वतन करना ठीक नही है और इससे सरकार का काम ठीक नही चल सकता है। स्पीकर साहब, यह भी देखने वाली बात है कि जिन माननीय सदस्यों जैसे चौधरी जगन नाथ है, चौधरी सतबीर सिंह है, ने आजादी के साथ काम करना चाहा, उनको किनारे लगा दिया गया। स्पीकर साहब, एक बात और कहना चाहता हूं कि आज मत्रिमण्डल मे पंद्रह सोलह मंत्री है और इन पंद्रह सोलह मे से दस के करीब ऐसे है जो मुख्य मंत्री मे वि वास नही रखते है। उनका मुख्य मंत्री मे किसी न किसी स्टेज पर अवि वास है। स्पीकर साहब, जिन मत्रिमण्डल मे दस ऐसे मंत्री हो जिनका मुख्य मंत्री मे वि वास न हो, वह मंत्रिमण्डल क्या काम करेगा ? खुद श्री मूलचंद जी, जोकि आज हरियाणा के वित्त मंत्री है, वे तायल साहब वाली सीट पर बैठ कर इन सभी बातों के लिये सरकार का विरोध किया करते थे कि इकोनोमी करे। भ्रश्टाचार के बारे मे

कहते थे कि यह बंद होना चाहिए और वजीरों के खर्चे मे कमी होनी चाहिए लेकिन आज वे स्वयं इन सारी बातों को मनवाने के लिये हाउस मे कह रहे है। और उन्होंने एक भाब्द भी आ वासन का यहां पर नही दिया है कि आगे के लिये ऐसी कोई बात नही होगी, ऐसी फिजूल खर्ची नही होगी।

स्पीकर महोदय, आज आप देखें कि वजीरों के खर्चे कितने बढ गये है और इन खर्चो के ऊपर कोई किसी प्रकार की पाबंदी नही लगाई गई है। हरेक मिनिस्टर इम्पोर्टिड कार के बगैर चलना पसंद नही करता । जितने भी मंत्री है तकरीबन हरेक के पास इम्पोर्टिड कार है। आप जानते है कि इन कारों की रिपेयर का इंतजाम हमारे यहां पर नही है क्योंकि इन कारों के पुर्जे हमारे यहां नही मिलते हैं दूसरे ये कारें महंगी मिलती है। इस तरह से इन पर बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। इसके साथ आपको यह भी ज्ञान होगा कि पैट्रोल का खर्चा भी इनका ज्यादा है और आज पैट्रोल के रेट्स मे भी इजाफा हो गया हैं इस तरह से इन कारों के ऊपर बहुत खर्चा हो रहा है। इस वक्त मैं बजट के बारे मे कुछ कहना नही चाहता, केवल यह कहूंगा कि एक तरफ तो लोगों पर टैक्स थोपे जा रहे हों और दूसरी तरफ मिनिस्टर गांव गांव मे कारों पर जाकर भाशण दे, यह बात उन के लिये भाोभा नही देती। वैसे तो भाई मूल चंद जी बड़े समाजवादी है, समाजवाद की घोशणा भी करते है लेकिन इन सारी बातों की तरफ पता नही उनका ध्यान क्यों नही गया? वे भी बड़ी कारों के बगैर सफर

करना पसंद नही करें तो अच्छी बात नही । बल्कि उन्हें तो एक मिसाल रखनी चाहिए कि वे दिल्ली जाएं तो बस मे ही आएं। तभी लोगों के ऊपर उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस खर्चे को कम करने के लिये थोड़ी बहुत उन्हें कोि ाश करनी ही चाहिये।

स्पीकर साहब, मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से मिनिस्टरों के विभागों मे परिवर्तन हो रहा है, विस्तार हो रहा है और जिस ढंग से इन सारी बातों पर खर्चा हो रहा है, इसका पब्लिक पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ने वाला नही है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछेक अखबारों के सम्पादकीय नोट, जिन मे उन अखबारों ने टीका टिप्पणी की है, यहां पर पढ़कर सूना दूं। यह ट्रिब्यून का सम्पादकीय हैं समय का ध्यान रखते हुए मैं इसका पहला पैरा छोड़ रहा हूं और जो काम की बात है वही पढूंगा।

"for years known as the "land of.....", Haryana has lately acquired the dubious distinction of having witnessed more ministrial changes, more exercises in apprearing dissibdents and accomodating party factions somehow, more last minute cancellations of swearing in ceremonies and more changes in portfolios than any other Janta dominated State. All these activities point to a queer situation in which virtually nothing is final and no one knows who will stay where and for how long....."

Mr. Speaker: That can also be taken as dynamism in the State.

चौधरी रिजक रामः डायनामिजम के बगैर तो कोई बात ही नही, स्पीकर साहब।

It further reads—

".....The amazing dgree of the consequential uncertainty in the polical set up greatly hampers the administration. It also invites derisive commet from the men in the street and, of course, from politioal rivals waiting in the wings. The latest swich by which the Finance ortfolio has changed hands for the third time in the past few months confirms the impression that the motivations for the frequent top level changes in Haryana are unrelated to merity, proprity and the principle of parliamentary government.

Mr. Devi Lal, the Chief Minister is reported to have told newsmen at Chandigarh on Sunday, "I had at first allotted finance to a Jat Mr. Satvir Singh Malik, then to a Rajput (Thakur Bir Singh), and now it goes to a Harijan (Mr. Preet Singh Rathi) because he too can run it".....

Why should a Jain remain outside?.....

श्री वीरेन्द्र सिंहः चौधरी साहब, यह तो इसमे नही है, यह तो आप अपनी तरफ से कह रहे है।

Chaudhri Rizaq Ram: It further reads—

".....Mr. Devi Lal also hinted at the possiblity of the other portolios bieng reshuffled in due course. Finance is a compled portfolio requiring a high degree of understandingunless, of course, the Minsiter in charge is to

become a more figurhead and all the budgetary exercises are to be done by the officers of the Finance Departemnt, without the Minister grasping the intricacies, muchy less suggesting modification or pointing out discrepancies.

Beside, if this portfolio is to be allotted on the basis f caste or faction and in an attempt to let may legislators acquire the feel of it, all M.L.As. belonging to the Janta Party both light weights and heavey weights, especially the dissidents, most of whom dictate their price for assured polical support may hope to occupy the ministerial chair before their five year term in over. A legislator has only to declare another switch inloyality assure full support to the leader and become a trumpteer almost overnight. The argument can be further extended. If the Finance Minister is to become for all practical purposes, a game of musical chairs and eachmember of the Haryana Cabinet is to become a polical rolling stone, the other portfolios (including Home, Education, Agriculture and Industries) should also be allotted for a short time to all the legislators in turn ont he basis of caste. After all if “A” can don the mantle for a few days, why not “B” and “C” and “D”? According to the Chirf Minister logic, evyone “can run it”. In France, until General Do Gaulle emerged on the scene, Minsters changed places so quickly and so often that people could not be sure who was in power and sho was not. Every third politician in the country could claim to be an ex Minister. In Haryana, too, each Ministers portfolio and the length of this tenure may depend on the role he plays int he recurring toppling drives which seem to have become a trandition. If this were to happen, the mess int he State would become even more terrible.”

This is from the editorial of the Tribune dated the 25th July, 1978.

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, टाईम काफी हो गया है। अब आप वाइंड उप करने की कोि ा ा करें।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मैं तो बोला ही बहुत थोड़ा हूं, इस टापिक पर मैं दो मिनट और बोलूंगां इसी सिलसिले मे, एक और दिनांक 11–8–78 के ट्रिब्यून मे छपे 'ओ चण्डीगढ़' के कालम को पढ़ देता हूं जिसको इस समय पढ़ना मुनासिब होगा। वह इस प्रकार हैः–

"One has heard of the poet who woke up one fne moring and found himself famous. One has heard also of the Indian otentate of the post who in a moment of happiness, appointed each of his subjects as a Minister. But not many are likely to have imaginedc that to become Ministers all that they needed to do was to land in a particular city. One truck driver according to a Haryana dissident leader cautioned another. "Don't go to Chandigarh. They'll make you a Minister". Does it mean that even truck driver dread the possibility of becoming Ministers in spite of the fact that they have one timng in common while the former are drunk the latter are power drunk? They really should not because once they become ministers they can own the trucks which they now drive. Besides, the policemen who now put obstackles in their way will line up all along the way they pass and salute them....."

इतना खतरा पैदा हो गया हे कि ट्रक ड्राइवर भी यह कहने लगे है कि चण्डीगढ़ मत जाओ आपको पकड़ कर मिनिस्टर बना देंगे। तो स्पीकर साहब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से कैबिनेट मे एक्सपैं ान नही होनी चाहिए और जो पोर्टफोलियोज मे परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव पब्लिक पर अच्छा नही पड़ेगा। चौधरी देवी लाल जी 21—6—77 को जब मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने यह घोशणा की थी कि वे राज्य मे स्वच्छ और निश्पक्ष भाासन चलाएंगे और भ्रश्टाचार को खत्म करने के लिये वे सारी ताकत लगा देंगे। स्पीकर साहब, भ्रश्टाचार नीचे भाुरू नही होता बल्कि ऊपर से चलता है। राव बीरेन्द्र सिंह जी ने बोलते हुए इस सदन के माननीय सदस्यों के बारे मे कुछ बातें कही थी और यह विचार जाहिर किया था कि माननीय सदस्यों को आफिस आफ प्रोफिट देकर पाबंद किया जा रहा है ताकि वे मुख्य मंख्य मंत्री को सहयोग देते रहें मैं उनकी इस बात से सहमत नही हूं। मैं यह मानने के लिये तैयार नही हूं कि इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य महज चेयरमैन बनने के लिये या दूसरी किसी रियायत के कारण सहयोग देने के लिये पाबंद हो जाये। आखिर वे सारे माननीय सदरू है, मानयोग सदस्य है और उनकी दयानतदारी पर इस किस्म के भाब्द कहना मुनासिब नही है। पीछे आपने देखा होगा कि कंवर राम पाल सिंह थे, स्वामी अग्निवे ा थे, ये दोंनो चेयरमैन थे और सुशमा स्वराज जी, सरदार तारा सिंह जी तथा श्री जगन नाथ जी मंत्री थें उस समय उनको हजारो रूपये अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता था, कारें मिली हुई थी और

कोठियां मिली हुई थी लेकिन इसके बावजूद भी जब इन्होंने देखा कि सरकार का काम ठीक तरीके से नही चल रहा है तो उन्होंने आवाज उठाई और अपने पद त्याग दिये। इसलिये अगर कोई यह ख्याल करता है तो उन्होंने आवाज उठाई और अपने पद त्याग दिये। इसलिये अगर कोई यह ख्याल करता है कि महज इन ओहदों के मिलने से कोई पाबंद हो जाता है, ऐसी बात नही है, ऐसा कभी हम सोच भी नही सकते। मुख्य मंत्री जी तो इस समय सदन मे नही है लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वे पिछले तजरबे की बिनाह पर इस गल्तफहमी मे न रहे। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे एम.एल.एज. को तजरबा देने के लिये चेयरमैन बना रहे है। इस बारे मे मुझे कोई आपत्तित नही है लेकिन अगर वे यह समझते है कि ऐसा करने से वे एम.एल.एज. सहयोग के लिये पाबंद है तो यह उनकी गल्तफहमी है। चौधरी भजन लाल जी यहां बैठे है, नये नये मिनिस्टर बने है जब उनको भी यह मालूम हो जायेगा कि सरकार का काम ठीक नही चल रहा है तो ये सब से पहले छोड़ेंग। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है कि वह उसी आदमी को मिनिस्टरी मे लेते हे जिसको वह तजरबेकार या योग्य समझते है। ठीक है मुझे कोई एतराज नही है, ले। लेकिन मुण्े एक बात की समझ नही आती कि मिनिस्टरी मे लेने के लिये इनकी परीक्षा का सटैंडर्ड क्या है? बाबू मूल चंद जी ने पीछे एक महीना सरकार की आलोचना नही की और वे मिनिस्टर बन गये। लेकिन एक अफसोस है कि जो दो दो साल से बैठे हुए है, पूरी

मेहनती भी है और इकोनोमी भी पूरी बरत रहे है, उनको नम्बर क्यों नही आ रहा है? स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि चौधरी भले राम जी है, संत कंवर जी है और मेरे पास चौधरी सतबीर सिंह जी बैठे है इतना तो प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन का भी तजरबा हे, इनको क्यो नही लिया जा रहा है? (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी रिजक राम जी भी कई साल तक मंत्री रहे है।

चौधरी रिजक रामः मेरे बारे मे भी सोच लेंगे और जैसा मुझे दोगे वह भी मुझे पता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो लोग दो दो साल से इंतजार कर रहे है, जिनकी काबलियत मे कोई कमी नही है उनको क्यों नही लिया जाता ? जैसे अभी देवेंद्र भार्मा जी ने एक प्र न के दौरान कहा कि अगर कोई कम्पीटैंट मिनिस्टर जवाब देना चाहे तो दे लेने दो, चाहे कोई नोअिस भी न हो। इसलिये मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट मे जो रिवालविंग तरीका निकाला है उसके हिसाब से ऊपर से लेकर नीचे तक जो योग्य मंत्री साबित हो उनको मुख्य मंत्री बना दो और जो काबिल चेयरमैन है उनको मिनिस्टर बना दो इसी तरह से इस सर्कल को चलने दीजिये.....(विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री वाली बात इन्होंने अपने लिये कही है क्योंकि इनका तजरबा भी काफी रहा है।

चौधरी रिजक रामः आपकी तजवीज का मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैं अपनी तरु से चौधरी भजन लाल जी के बारे मे ज्यादा सोच रहा हूं। स्पीकर साहब, ये बिल्कुल योग्य आदमी है और किसी मैंबर के बारे मे गल्त कहना ठीक नही होता (विघ्न) लेकिन मैं एक बात कहना चहाता हूं कि एम.एल.एज. को इस तरह से ओहदे देने से पब्लिक पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं हमारे एम.एल. एज. इस प्रकार करेंगे तो उसका पब्लिक पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं हमने पब्लिक के सामने एक मिसाल रखनी है। लोगो को, हम लोगा से आ ाएं हे इसलिये हम सभी को चाहिए कि एक एक मैंबर जगह जगह जाये और लोगा की बाते सुने। यहां तो किसी को मिनिस्टर बनने की लगी हुई और कोई किसी कारपोरे ान का चेयरमैन बनने का उतावला है क्योंकि कएक चेयरमैन के पास कारें है और कोठियां है। इस के साथ साथ हमें लोगों कील कठिनाईयों को भी दूर करना है। इस तरह बैठने से इसका पब्लिक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्पीकर सहाब, अब मैं प्रौढ़ ि ाक्षा के बारे मे मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे हरियाणा मे इस प्रकार के प्रौढ़ ि ाक्षा के तीन सौ सैंटर खोले गये है। मैं स्पीकर महोदय, कहता हूं कि इसके लिये सरकार ने जो रूपये रखे है वह फिजूल रखे है। में सरकार से सिर्फ एक बात

अर्ज करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो फरमाया कि लड़कियों को आई एंड क्राफ्ट की ि ाखा दी जायेगी, वह ठीक है। उन्होंने यह भी बताया कि इन प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिये आठवीं, दसवीं तथा बी.ए. पास ि ाक्षकों को लगा सकते है। मेरी सरकार से अर्ज है कि जो देहात मे बेकार पढ़े लिखे लोग है उनको इनकी ि ाक्षा के लिये लगाया जाये। हमारी सरकार तो यह चाहती है कि गांवो मे वे पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख जाये, वे साक्षर हो जाये, यह दूसरी बात है। परंतु मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चहता हूं कि यह प्रौढ़ ि ाक्षा का कार्यक्रम आज से नही कई साल पहले से भ्ारू हुआ है। सरकार को यह चाहिए कि वह हर क्षेत्र मे माहिर लोगो को एक्पर्टस को, अच्छे अच्छे आदमियों को चोटी के आदमियों को गांवो मे ट्रेनिंग देने के लिये भेजे। हमारे लोगो को खती के काम के बारे मे जानकारी की आवरूयकता है, स्वास्थ्य की जानकारी की आव यकता है। उनको बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार खाद का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए इंडस्ट्री मे एक्सपर्टस को गांवों मे जाकर लोगो इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देनी चाहिए। आर्टिजंस को जो उनको अपना पु तैनी काम है उनके बारे आजकल की नई चीजों द्वारा उसको बढ़ाने की ट्रेनिंग दे। उनको उनके काम की नई टैक्नीकस के बारे मे बताये कि किस प्रकार नई चीजों का प्रयोग करना है। जो मजदूर आर्टिजंस है उनको किस प्रकार ट्रेंड करना है, चाहे किसी गरीब मजदूर को ट्रेनिंग देनी है, चाहे प्रौढ़ों को साक्षर करना है या किसी आर्टिजन को ट्रेंड करना है या किसी

किसान को खेती के बारे मे ज्ञान देना है या इंडस्ट्री को फैलाने के लिये इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देनी है इन सब का नतीजा क्या निकलता है। आप सब यहां आठवीं दसवीं पास बैठे है, आप क्या देखेंगे, आप अपने बच्चों का नतीजा देखे वहां भी आठवीं दसवीं से ज्यादा क्या कोई ि ाक्षा प्राप्त कर रहा है ? आप अपने स्कूलों की पढ़ाई की ओर ध्यान देन कि प्रौढ़ ि ाक्षा की ओर। प्रौढ़ ि ाक्षा तो जैसा कि मैंने बताया, लोगों को उनकी ट्रेड के बारे मे जानकारी दे कर हमे दे सकते है लेकिन बच्चों की पढ़ाई की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। इसलिये मैं बार बार कहूंगा कि प्रौढ़ ि ाक्षा के लिये जो पैसा रखा गया हे यह सरकार की फिजूल खर्ची है। तो मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे। आखिर मे मैं इस बात के साथ खत्म करता हूं कि फ्लड रिलीफ के बारे मे सरकार ने काफी मेहनत की है और फ्लड एफैक्टिड एरियाज को पूरा रिलीफ दिया है। चौधरी प्रीत सिंह जी ने रिलीफ फंड के बा मे जो बताया है वह काफी संतोशजनक है। .....(विघ्न).....तो अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिन इलाकों में फ्लड आये उन इलाकों के लोगों की हालत बहुत खराब है अब फिर इन इलाकों मे ओले पड़ गये है। जनाब, यह तो कुदरत की कैलेमिटी है सबके लिये मु ि ाकल है, आपको भी मु ि ाकल है। दूसरी बात इस बारे मे यह कहना चाहता हूं इन इलाकें के लोगो ने कोआप्रेटिव सोसाइटियों से या ने ानेलाईज्ड बैंकों से जो लोन लिया है, उसको माफ किया जाये और उन लोगो को और लोन दिलाया जाये। पिछली बार इस इलाके के

लोगो की फल बाढ़ से खराब हो गई थी और अब की फसल ओलो से खराब हो गई है। अध्यक्ष महोदय इस बात की ओर आप ख्याल फरमायें कि जिस किसान की पिछले साल की फसल खराब हो गई और इस साल की फसल भी ओलो से खराब हो गई, क्या वह गरीब किसान बैंक का कर्जा या तकाबी को अदा कर सकेगा ? उसको तो अपनी जरूरयिात को ही पूरा करना मु ाकल हो रहा है तो इन हालात मे क्या वह कर्जा उतार सकेगा ? मजदूर जिनके घरबार गिर गये, सारी की सारी बस्तियां तबाह हो गई, उनसे जब बैंक वालों की या कोआप्रेटिव सोसायटियों के कर्जे की अदायगी पूरी नही हुई तो वे उनकी कुर्की करने आ गये। इस तरह जिसन कर्ज लिया है उस के साथ उसके घर के अन्य सदस्य भी मारे जाते है।

Mr. Speaker: That will aouunt to punishing those peole who are not taking any loan.

चौधरी रिजक रामः मेरी सरकार से गुजारि ा है कि जिन्होंने इन नै ानेलाईजड बैंको और सोसायटियों से लोन ले रखा है उसे पोस्टपोन कर लिया जाये। पोस्टपोन करने के लिये इसलिये कहा है क्योंकि अभी पिछली वसूली तो पूरी नही हुई है। जैसे वीरेन्द्र सिंह जी ने भी कई जगह का बताया है, जहां जहां कैलेमिटी का प्रभाव पड़ा है, फ्लड आये है या ओले पड़े है। उन लोगो की कैपेसिटी देखकर वसूली की जाये। इन इलाकों मे आपके आफिसर्ज है, उनका स्टाफ है। ववह ये देखे कि जो लोग

कर्जा अदा नही कर सकते है उनकी हालत को देख कर वे उनके कर्जे माफ करने की सिफारि ा करे। इन कोआप्रेटिव सोसायटियों और बैंकों के पास आठ या दस लाख रूप्ये के ऐसे फण्डज होते है। जिनमे से ये इस पूरी न होने वाली अदायगी को पूरा कर सकते है। तो मेरी सरकार से अर्ज है कि इन कर्जो को माफ कर दिया जाये और लोगो की मदद की जाये। आपकी सरकार असैस करे कि इस इसमे कितना बोझ सरकार पर पड़ेगा। बजाये असैस करने के, आपके अधिकारी या कर्मचारी इन लोगो को कर्जे की अदायगी ने करने पर गिरफ्तार करते है, उनके घरों की कुर्की करते है, यह नही होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आपने काफी टाईम ले लिया है। अब आप अपनी स्पीकच वाइंड अप करें।

चौधरी रिजक रामः मैं इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हूं।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्षः मेरी आप सभी मैंबर्ज से अर्ज है कि सभी पांच पांच मिनट बोले। जो साहिबान गवर्नर एड्रैस पर बोल चुके है, काफी समय ले चुके हे वे कम समय लें ताकि जिनको समय नही मिला है उनको भी समय मिल सके। I would, therefore, like

to give time to those who have not spoken on the Governor's Address.

श्रीमती सुशमा स्वराजः (अम्बाल छावनी): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुमानों की इस तीसरी किस्त के माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जो करोड़ रूप्ये की रा ि ा.....

श्री अध्यक्षः आप कौन सी डिमांड पर बोल रही है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड बताती हूं। जो टोटल सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस यहां पर रखे गये है, उनके माध्यम से 35.95 करोड़ रूप्ये की रा ि ा सदन मे पास करवाने के लिये रखी गई है। वैसे तो मैं चौधरी रिजक राम जी की इस बात की ताईद करती हूं कि यह कोई स्वस्थ परम्परा नही है कि 36 करोड़ रूप्ये की रा ि ा जो कि स्वयं मिनी बजट हो जाती है उसको इस तरह से खर्चे कर लेने के बाद सदन मे पास कराने के लिये लाया जाये। यह महज एक रस्मी रिवायत है। अध्यक्ष महोदय, इस 369 करोड़ रूपये मे से, जिसकी तफसील का ब्यौरा मैंने पढ़ा है, हर विभाग की मांग संख्या के अंदर कुछेक रा ि ा इस तरह की है तो कि सरकारी कमैचारियो को महंगाई भत्ते के रूप मे दी गई है । मैंने सारी रा ि ा को अलग अलग जोड़ा तो यह कुल मिला करके डेढ़ करोड़ रूप्ये के करीब बनती है जो हमने सारे विभागों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की दो किस्तों के रूप मे दिया है। इसमे कोइ एतराज नही हो सकता। अध्यक्ष महोदय, जब चीजों की कीमत मे वृद्धि होती हे तो उसके साथ साथ सरकारी

कर्मचारियो का भी बजट बढ़ता जाता है। उनको मंहगाई भत्ता मिलना ही चाहिए। मैं नही समझती कि इसमे किसी सदस्य को कोई एतराज होगा। लेकिन इसके साथ साथ मांग संख्या 2, 4, 8, 9, 13 और 25 इन पर में अपने कुछेक ख्यालात का इजहार करना चाहूंगी। मांग संख्या 2 के अंदर एक मद आती है डिग्री की रा ि ा 2 हजार 90 रूप्ये की बहुत कम रा ि ा है लेकिन रा ि ा इसमे ज्यादा महत्व नही रखती है, महत्व रखती है एक अफसर की लापरवाही। अध्यक्ष महोदय, इस रा ि ा के तहत मैं कहूंगी कि सौ सौ रूपये का सौ नोट का एक बंडल किसी आदमी को मिला और उसने उसे हांसी के एस.डी.ओ. (सिविल) को सौंप दिया। उस आदमी ने कहा कि मुझे तो यह रास्ते मे पड़ा हमला है, यह पता नही किस का है। एक दूसरे आदमी ने दावा किया कि यह पैसा मेरा है लेकिन एस.डी.ओ. (सिविल) ने कहा कि एविडैंस प्रोपर नही है इसलिये यह पैसा तुम्हें नही दिया जायेगा। बाद मे उस आदमी ने कोर्ट मे दावा कर दिया। कोर्ट ने फैसला विद कास्ट उस आदमी के हक मे किया यानी वह रा ि ा जो सरकारी खजाने मे जमा करवाई गई थी वह तो वापिस करनी ही पड़ी लेकिन उसके साथ साथ 2 हजार 90 रूपये की रा ि ा कास्ट के रूप मे सरकार को देनी पड़ी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एस.डी.ओ. (सिविल) छोटा–मोटा अफसर नही, स्वयं एस.डी.ओ. होता है। वे स्वयं भी ऐसा एविडैंस ले सकते थे जो कि जुडि ियल मैजिस्ट्रेट ने लिया यानी उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से उस पैसे को जमा करवाया। प्रोपर एविडैंस लेने की कोि ा ा नही की और

डायरैक्ट वह पैसा जमा करवा दिया। अगर थोड़ी सी परवाह करके, थोड़ी सी जिम्मेवारी से इस चीज के ऊपर वह एविडैंस कलैक्ट करने की कोि ा ा करते तो यह 2 हजार 90 रूपये का जो एक अफसर द्वारा व्यर्थ खर्च सरकार के सिर पर प्ड़ा हे इससे बचा जा सकता था। मैंने पहले कहा था कि रा ि ा इतना महत्व नही रखती जितनी कि अफसर की गैर जिम्मेदारी। इसलिये मैं यह सुझाव सदन के सामने रखना चाहती हूं कि.....

Mr. Speaker: Perhaps some actionmight have been taken against that officer.

वित्त मंत्री (श्री मूल चंद जैन): यह तो कांग्रेस के जमाने की बात है, जनता पार्टी के टाईम की नही।

श्रीमती सुशमा स्वराजः सवाल जनता और कांग्रेस पार्टी का नही है। सवाल अफसर का है। अफसर तो अब भी वही है जो कांग्रेस के जमाने मे थे। (ाोर)

श्री अध्यक्षः यह आप कैसे परज्यूम कर सकती है कि उसके खिलाफ एक ान नही लिया, भाायद उसके खिलाफ भी आव यक कार्यवाही की गई होगी।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस मे यह तो कहीं नही लिखा है। मांग संख्या 2 के तहत जो डिस्क्रि ानरी ग्रांट का सवाल आया है उसके ऊपर बहुत तफती ा से चौधरी रजक राम जी ने बताया है। मैं इसके बारे मे

इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे बड़ा दुख होता है कि आज हमारे मंत्रियों के खर्चे काफी बढ़ गये है। एक बात हो अहम तोर पर मेरे सामने है वह यह है कि आज हमारे मंत्रिमण्डल मे एक भी मंत्री ऐसा नही है जो सरकारी मकान मे रहता हो। उन्होंने प्राइवेट कोठियां ले रखी है। जो कोठियां पुरानी किराये पर ली हुई है, उनमे तो मंत्री रहते ही थे लेकिन जो मंत्री अभी नए बनाए गए है उनमे से भी किसी ने वह सरकार कोठी लेना स्वीकार नही किया और हर एक मंत्री ने बाहर 1500 रूपये से लेकर 2000 रूपये तक का मकान ले करके रहना स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारि ा करना चाहती हूं कि पंजाब और हरियाणा..... (विघ्न).....

श्री भले रामः आप भी तो ऐसी कोठी मे ही रहती थीं.....

श्रीमती सुशमा स्वराजः भले राम जी आप ने अच्छा किया यह बात कह दी। मैं सदन को बद दूं कि मैंने सरकारी कोठी ली थी और मैं वह भी लेने के लिये तैयार नही थी। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री महोदय को यह बात कही कि आप मुझे एम.एल. एज. फ्लैटस मे जगह दे दीजिए और एम.एल.एज. फ्लैटस मे रह लो.....(ाोर)..... एम.एल.एज. फ्लैट नम्बर 26 मुझे अलाट हो चुका था और मंत्री बनने के बाद भी मैंने कहा कि मुझे फ्लैट मे रहने दिया जाये.....

Mr. Speaker: Please stick to the demand.

श्रीमती सुशमा स्वराजः उन्होंने कहा कि आप रह लीजिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हाउस कमेटी (ाोर)

Mr. Speaker: I would request you to stick to the demand.

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड पर ही कह रही हूं कि जब कोई मंत्री कोई आफर करता है और खर्चा घटाना चाहता है तो दूसरी तरफ हाउस कमेटी की चिट्ठी आई और रिटन मे वह चिट्ठी मेरे पास है जिसमे कहा गया हे कि विधान सभा के नियम इतने इतने के अंतर्गत कोई मंत्री एम.एल. एज. फ्लैटस मे नही रह सकता। इसलिये मुझे सरकार कोठी नम्बर 68 अलाट की गई। फिर मुझे मुख्य मंत्री महोदय ने बुला करके कहा कि चला छोटी कोठी है अगर किसी नियम के अंतर्गत वे फ्लैट लेने नही देना चाहती तो तुम कोठी मे चली जाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चहाती हूं कि पंजाब सरकार के मंत्री उन कोठियों मे रहते हे और सरे बड़े कुनबे वाले, मंत्री बनने से पहले छोटे घरों मे रहते आए है। क्या बा हे कि मंत्री बनने के बाद उनकी नाक के नीचे इस तरह की कोठी नही आती है ? (विघ्न) मैं वही बात कहना चाहती हूं और मुझे इस बात का अफसोस है, भाई संत कंवर जी जिसकी तरफ इ ाारा कर रहे है मुझे इस बाम का अफसोस है कि श्री मूल चंद जैन जी जो मेरे बुजुर्ग है, कम से कम वे तो इस बाम को साबित कर सकते थे।

जैन साहब स्वयं वित्त मंत्री है। बजट ला रहे है, लोगो के ऊपर टैक्स लगा रहे है। खुद इन्होंने 2200 रूप्ये की कोठी ली है। 200 रूपया अपनी जेब से डालते है और 2000 रूप्ये सरकार देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिये कह रही हूं कि जब यह बजट आता हे तो जितनी तवज्जुह हम टैक्स लगा करके, कर लगा करके पैसे वसूल करने पर देते है उतनी ही तवज्जुह हमें बजच कर देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी मे एक कहावत है 'A penny saved is a penny earned." एक पैसे की बचत करे तो उससे भी हमारे राज्य के कोश का बोझ घट जाता है लेकिन न मालूम आज कैसे रिवायत हो गई है। पंजाब सरकार के मंत्री उन कोठियों मे रह रहे है बल्कि 5–6 मंत्री हमारे घर के सामने रह रहे है लेकिन हरियाणा सरकार का कोई भी मंत्री वहां नही रह रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं कि उन कोठियों मे सरकारी अफसर रह रहे है और वह अफसर उन कोठियों को मेनटेन नही कर सकते। नीचे की सारी कोठी खाली रहती है उस कोठी के लिये यह पर्याप्त पौधे भी नही लगा सकते है। वहां के लांच बिल्कुल उजड गये है। वे उन लांज को मेनटेन नही कर सकते। लेकिन हमारे मंत्रियों के नाम के नीचे वह कोठी नही आती। वह बाहर 2–2 हजार की कोठी ले करके सरकार के ऊपर बोझ बन रहे है।

Mr. Speaker: Please wind up now.

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, एक बात थोड़ी सी मांग संख्या 9 की कह दूती हूं क्योंकि उसके बारे मे मेरा एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव भी डिस्अलाऊ हो गया है।

श्री अध्यक्षः कन्क्ल्यूडिंग रिमार्क्स पर आ जाइये।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कहा था कि मुझे 5 मांगों पर बोलना है लेकिन समय बहुत कम है इसलिये केवल मांग संख्या 9 पर, जिसमे 28 गैर सरकारी कालेजिज को अनरक्षण अनुदान देने की बात है, अध्यक्ष महोदय, 4335600 रूपया गैर सरकार कालेजिज को ग्रांट के तौर पर दिया जाना है जिससे उनका घाटा पूरा हो सके। आज मुझे दुख हुआ कि मेरा एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव, जो कि डी.एस.डी. कोलेज पर था, इसी मतलब को ले करके डिसअलाऊ हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग को चलैंज नही कर सकती इसलिये मैं उसका जिक्र नही कंरूगी लेकिन इतना जरूरी कहूंगी कि अगर मेरे काल अटैन ान मो ान का स्वयं ि ाख मंत्री जी जवाब नही दे सके तो कम से कम इस मांग के ऊपर बोलते हुए ि ाक्षा मंत्री जी जरूर जवाब दे। मैं उनसे केवल इतना ही कहना चहती हूं कि जब वह 4335600 रूपये गैर सरकार कोलेजिज के घाटे को पूरा करने के लिये देना मान भी गये है लेकिन इस के बावजूद भी आज गैर सरकार कालेजिज की काली हालत सुधरी नही है, आज भी ि ाक्षक भूख हड़ताल और धरना लगा करके अपनी मांगों को मनवा रहे है, तो मैं उनसे यह गुजारि ा कंरूगी कि जब यहां पर

यह मांग उठती है कि उत्तर प्रदे ा के नमूने पर आप ट्रेजरी के जरिये तनख्वाह देने की बात मान लो तो इसमे क्या हर्ज है ? ऐसा करने से आप वर्क आउट करके यह तो देखे कि कितना पैसा ओर उन्हें देना पड़ेगा। इससे अगर थोड़ा सा ज्यादा बोझ सरकार के ऊपर पड़ता भी है तो 75 फीसदी घाटा तो हम पहले ही पूरा रहे है और अगर थोड़ा सा खर्चा और पड़ता है तो वह हम उनसे ले सकते है ?

श्री अध्यक्षः यह तो आप खुद वर्क आउट कर सकती है 75 परसैंट यह आता है और बाकी क्या आता है ?

श्रीमती सुशमा स्वराजः 80 प्रति ात कालेजो की फीस का ले लिया जाये और उस मे 5–7 लाख रूप्या और डालना पड़े तो डाल ले और अध्यापकों की लौंग स्टैंडिग डिमांड का समाधान करे। 5–7 लाख रूपये और भाामिल करने से समस्या का सामधान हो जायेगा, बच्चों को ि ाक्षा मिलने लगेगी और राज्य को भी लाभ होगा। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यू.पी. पैट्रन पर अध्यापकों को तन्खाह देने के लिये प्रयत्न किया जाये। बजाये इसके कि सारा पैसा मैंनेजमैंट के सुपुर्द कर दें और मैनेजमैंट उस पैसे का सही उपयोग न करके इधर उधर गलत कामों मे लगाकर खुर्दबुर्द कर दे, यह अच्छा नही होगां स्पीकर साहअ, आपसमरूा को हल करने की कोि ाश करे, इतना कहकर मैं अपना स्थान लेती हूं।

श्री भले राम (बड़ौदा–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं डिमांड संख्या 1 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। एडमिनिस्ट्र ान पर जो खर्चा बढ़ाया या घटाया जाता है, यह घटाना बढ़ाना मुख्य मंत्री जी के अधिकार मे आता है और यह उन्ही के ऊपर निर्भर करता है। आप जानते है, हरियाणा मे कितने ही डिवैल्पमैंट के कार्य हो रहे है, कहीं पर नहरें पक्की हो रही है, कहीं पर अनाज बढ़ाने के उपाय किये जा रहे है, कहीं पर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का यत्न किया जा रहा है। ये डिवैल्पमैंट के कार्य हरियाणा की तरक्की के चिन्ह है और इस तरक्की के साथ साथ खर्चा बढ़ना जरूरी है.....

श्री अध्यक्ष: आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे है?

श्री भले राम: मैं डिमांड नं. 1 पर बोल रहा हूं। (व्यवधान) स्पीकर साहब, चोधरी रिजक राम जी ने कहा था कि जब किसी मिनिस्टर को किसी महकमे का तजर्बा होता है तो महकमा बदल देते है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि महकमे इसलिये बदलते है क्योंकि उनको तजर्बा हो जाता है और उस तजर्बे का फायदा दूसरे महकमे को होता है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, ज्यो ही चौधरी भले राम जी ने अदला बदली की बात कही, चोधरी रिजक राम जी फौरन अंदर आ गये (हंसी एवं व्यवधान)।

श्री भले रामः इनकी तो वह बात है, जैसे कोई बारात कही जा रही थी। एक आदमी ने पूछा कि बारात मे कौन कौन आदमी जा रहा है? उसने बता दिया कि पोहलू, भोलू वगैरह वगैरह जा रहे है इस तरह 8–10 आदमी गिना दिये। थोड़ी देन के बाद उसने फिर पुछ लिया कि और कौन कौन जा रहा है ? उस ने फिर कुछ बता दिया। इसके थोड़ी देर बाद फिर पूछ लिया कि और कौन कौन जा रहा है? तब उसने कहा कि आप भी जा रहे है, तब जाकर उस आदमी की तसल्ली हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप कौन सी डिमांउ पर बोल रहे है ?

लोक निमार्ण मंत्री (श्री लछमन सिंह): यह तो मिनिस्टरी मेकिंग की डिमांड है (व्यवधान)

श्री भले रामः इसलिये मैं कहना चाह रहा हूं कि खर्चा हुआ हे यह उचित है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कई मैंबरों को चेयरमैन बना दिया। मैं इन्हें बताना चहाता हूं कि एम.एल.ए. एक जिम्मेदार आदमी होता है और पब्लिक को जवाबदेह होता है। ये जो आई.ए.एस. आफिसर होते है, ये डिपार्टमैंट मे गड़बड़ करते है इन लोगों को चैक करने के लिये ही चीफ मिनिस्टर साहब ने इन एम.एल.एज. को चेयरमैन बनाया है..... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, आदणीय एम.एल.ए. साहब ने आई.ए.एस. आफिसर्ज की इंटैग्रिटी पर डाउट किया है, * * * * * । आई.ए.एस. अफिसर ज्यादा गड़बड़ नही करते.....

श्री अध्यक्ष: भले राम जी आप खत्म कीजिए।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, * * * * * * * * * * * * (व्यवधान)

श्री भले राम: मेरा कहने का मतलब यह नही था कि मैं आफिसर्ज की इंटैग्रिटी पर डाउट करता हूं। (व्यवधान) हमारे आफिसर्ज बहुत बढ़िया आफिसर है, लेकिन कभी कभी काम मे ढोल करते है, एम.एल.ए. चूंकि फ्री होता है, इसलिये इनकी चैंकिंग कर सकता है, इसलिये मैंने कहा था। (व्यवधान)

चौधरी गंगा राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर । स्पीकर साहब, श्री देवेन्द्र भार्मा ने यह कहा * * * * * और चौधरी राम लाल जी ने इसके जवाब मे कहा कि * * * * * * (व्यवधान)

श्री भले राम: मैं कह रहा हूं कि एम.एल.ए. जिम्मेदार आदमी है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, चौधरी रिजक राम ने कहा कि कई एम.एल.एज. को चेयरमैन बना दिया है और खर्चा

बढ़ाया है। यह गलत बात है। चीफ मिनिस्टर सहाब जितने चेयरमैन बनाना चाहे वे बना सकते है, यह उन्होंने देखना है कि काम कैसे चल सकता है (व्यवधान) अगर चीफ मिनिस्टर साहब चाहे कि तुम एम.एल.ए. की सीट से इस्तीफा दे दो तो वे भी दे सकते है। चीफ मिनिस्टर साहब जिसको भी चेयरमैन बनाना चाहे बना सकते है। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं और जो खर्चा किया जा रहा है, यह उचित है ओर यह मुख्य मंत्री की मर्जी पर निर्भर करता है।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं. 2, 3, 8, 9 तथा 11 पर अपने विचार रखना चाहता हूं । डिमांड संख्या 3 मे तकरीबन 80 लाख रूपये की डिमांड, पुलिस डिपार्टमैंट की एक्सटैं ान के लिये की गई है। इसमे कोई भाक नही कि आबादी के लिहाज से जरायम बढ़ रहे है और जरायम की रोकथाम के लिये पुलिस का बढ़ना जरूरी है। लेकिन स्पीकर साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी पुलिस बढ़ने के बावजूद भी दिन प्रति दिन चोरी, डाके बढ़ते जा रहे है और जो पुलिस आफिसर है, इन बुराइयों को रोकने के लिये कोई रूचि नही लेते बल्कि लोगो को गलत तरीके से प्रैस करते है, उन पर झूठे केस बनाते है। इस काम के बदले मे उन लोगा का प्रमो ान किया जाता है। (इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य, चौधरी खर ीद अहमद पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, मैंने बोलते हुए हाउस मे कहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो

नारा दिया है भ्रश्टाचार खत्म करने का, अगर उन्हीं के पालिटिकल आदमी भ्रश्टाचार करते है और उनके खिलाफ यहां पर पब्लिक के नुमायंदे आवाज उठाते है तो उन नुमायंदों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। चेयरमैन साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने एक बहुत बड़ा भ्रश्टाचार जो होने जा रहा था, उसको रोकने के लिये कोि ा ा की लेकिन उसके परिणामस्वरूप हमारे ऊपर बहुत से मुकद्दमें बने। उसकी हमें कोई चिंता नही है लेकिन मैंने हाउस मे जो कहा था उसकी तरफ सरकार ने ध्यान नही दिया। (विघ्न) मुकद्दमें पालिटिकल आदमियो पर बनते है, इसकी हमे कोई तकलीफ नही हे लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, मेरे खिलाफ 1700 रूपये के कपड़े की चोरी का 379 का मुकद्दमा बनाया गया। चेयरमैन साहब, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की बाम नही है। मैंने उस दिन डिप्टी स्पीकर साहब से भी प्रार्थना की थी कि आप किसी निश्पक्ष आदमी से इसक बारे मे इंक्वायरी करवाए। आज भी मैं वही बात आपसे कहता हूं। मैं इस हाउस के सामने दावे से कहता हूं कि अगर सिकी किस्म का ऐलीगे ान साबित हो जाये तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। चेयरमैन साहब, इस 379 के केस मे, रिकवरी करने के लिये पुलिस रिमांड मांगती रही, हमें परे ाान करती रही, हम सरकार को लिखते रहे लेकिन बजाये उन अफसरों के खिलाफ एक ान लेने के उन को प्रमो ान दी जाती है। कितनी अजीब बात है ? चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि ऐसे अफसरो के ऊपर सरकार खर्च न करे। चेयरमैन साहब, मैं आपका ध्यान एक बात

की ओर और दिलाना चाहता हूं। हमारे जिला जींद मे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर चीफ जुडीि ायल मैजिस्ट्रेट के घर पर चोरी हुई । ए.आई.जी. (सी.आई.डी) की जींद पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाउस मे चोरी हुई। इसके अलावा एस.डी.ओ. (पी.डब्ल्यू.डी.) की कोठी पर जो चोरी हुई, जो डाका डला, उसकी स्टोरी अगर आप सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जायेंगे। कोठी के अंदर मियां बीबी को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा गया, उसकी बहिन को भी पीटा गयां यहीं बस नही, बीबी को जंगल मे ले जा करके रेप किया गया जहां उसे बेहो ा हालत मे पाया गया। उसके घर मे जितना सामान था, जेवर था वह सब चोरी हो गया। चेयरमैन साहब, मुलजिम जो थे वे कहीं महेंन्द्रगढ़ मे पकड़े गये। 18 तोले जेवर था लेकिन पांच तोले की रिकवरी करके चालान पे ा कर दिया गया। 13 तोले जेवर और 1500 रूपये कै ा पुलिस ने अपने पास रखे। कई बार इसके बारे मे कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नही, कोई रिकवरी नही। अगर पुलिस ने इस तरह से काम करने है और पुलिस के महकमे मे गलत काम करने वालो को प्रमो ान दी जानी है तो ऐसा खर्च सरकार न करे।

श्री सभापतिः अब आप वाईंड अप कीजिए।

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, मुझे समय ही क्या मिला जो मैं वाईंड अप करूं?

श्री सभापतिः पांच मिनट का समय फिक्सड है, वह आप ले चुके है।

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, मैं आपका ध्यान डिमांड नं. 8 की तरफ दिलाना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, जब से जनता पार्टी की सरकार हरियाणा मे बनी है तब से एक किलोमीटर सड़क भी हमारे हल्के मे नही बनी है। ऐसा भेदभाव नही होना चाहिए।

श्री लछमन सिंहः आपका कौन सा हल्का है ?

श्री मांगे राम गुप्ताः जींद।

श्री लछमन सिंहः जींद तो सारा सड़कों से जुड़ा हुआ है।

श्री मांगे राम गुप्ताः ऐसी बात नही है।

श्री सभापतिः कोई पर्टिकुलर रोड़ आप बता दे।

श्री मांगे राम गुप्ताः मैं बता देता हूं । यह बड़ी खु ाकिस्मती की बात है कि मंत्री महोदय मौके पर आ गये। मेरे हल्का जींद मे एक गांव बराकलां है जो जींद से गोहाना रोड़ जाते हुए आठ किलोमीटर है और सफीदों रोड़ से जाने पर 14 किलोमीटर है। सरकार ने सफीदों रोड़ से मनुरपुर गांव से इस गांव को मिलाने की कोि ा ा की लेकिन बीच मे सुन्दरपुर गांव

पड़ता है जो गवर्नमैंट के रिकार्ड मे गांव नही है जिसकी वजह से वहीं तक यह सड़क रह गई।

श्री लछमन सिंहः उसकी आबादी कितनी है ?

श्री मांगे राम गुप्ताः उसकी आबादी तीन सौ की है।

श्री लछमन सिंहः वह ढानी होगी।

श्री मांगे राम गुप्ताः वह है तो गांव लेकिन सरकार के रिकार्ड मे नही है जो मेरा कसूर नही है।

चौधरी लाल सिंहः चेयरमैन साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर । इस किस्म के हल्के मे 35 गांव है जो रिकार्ड मे नही है और वहां कोई सड़क नही है।

श्री सभापतिः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है । मांगे राम जी अब आप त ारीफ रखिए।

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, यह हमारी तरफ से कोई आदमी नही बोलेगा। इसलिये आप मुझे थोड़ा सा टाईम दे दीजिये।

Mr. Chairman: Please wind up.

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, आपके द्वारा मैं मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस गांव को जल्दी से जल्दी सड़क के साथ जोड़ा जाये।

Mr. Chairman: Now you please take your seat.

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्री मूल चंद जैनः चेयरमैन साहब, जैसा तय हुआ था उसके हिसाब से अब तो मुझे बोलना है।

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, मैं केवल आधा मिनट लूंगा।

Mr. Chairman: No please. You take your seat now. The Finance Minister is to speak.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन सहाब, टाईम ऐक्सटैंड कर लिया जाये।

Mr. Chairman: I am going according to the plan givenby the Hon. Speaker. Please take your seat.

श्रीमती सुशमा स्वराजः चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब ने यह कहा था कि गिलोटी न 12.40 पर लगेगा। अभी तो 12.25 हुए है और गिलोटीन लगने को पंद्रह मिनट बाकी रहते है। ये पन्द्रह मिनट सदन के सदस्यों को बोलने के लिये दे दिए जाये।

Mr. Chairman: The Finance Minister will have to finish before the Guillotine is applied.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन साहब, यह बड़ा इम्पोर्टैंट मैटर है। इसमैं हरियाणा के फाईनैंस का सवाल है। यह हमारे हरियाणा की जनता की खून पसीने की कमाई है। (विघ्न)

Mr. Chairman: Mr. Pohloo, you are speaking without my permission. Please take your seat.

वित्त मंत्री (श्री मूल चंद जैन): चेयरमैन साहब, 35 करोड़ 95 लाख रूपये का यह सप्लीमैंटरी बजट है लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि जिन माननीय सदस्यो ने इन मांगों पर अपने विचार व्यक्त किये है उन्होंने इन मांगो के संबंध मे न तो विस्तार से हाउस के सामने कोइ बात रखी और न ही यह सुझाव दिया कि किस तरीके से ये मांगे 1978–79 के बजट मे आ सकती थी। (विघ्न)

स्वामी आदित्यवे ा: सभापति जी, वित्त मंत्री जी जवाब देने के लिये खड़े हुए है या अभी वैसे ही बोल रहे है ?

श्री सभापति: जवाब देने के लिये खड़े हुए है।

स्वामी आदित्यवे ा: हमें तो टाईम ही नही मिला।

श्री सभापति: क्या करे टाईम की पाबंदी है। (विघ्न)

श्री मूल चंद जैन: चेयरमैन सहाब, मैं हाउस का समय उन जीजी एतराजात पर नही लेना चाहता जिनमे चौधरी रिजक राम जी ने अपना समय लगाया कि यह कैबिनैट किस तरीके से बनी। यह पालिटीकल बातें थी। इसका इन अनुमानों से कोई संबंध नही। मैं मानता हूं कि मिनिस्टरों की तादाद बढ़ी लेकिन इस तादाद बढ़ने से इस 35 करोड़ 95 लाख का बजट मे केवल 10 लाख रूप्ये की मांग हाउस के सामने आई जिसमे मत्रियों की

डिसक्रि ानरी ग्रांअ भी भाामिल है। (विघ्न) चेयरमेन साहब, यही नही 2090 रूपये की एक छोटी सी मांग को एक बड़े महत्व का प्र न बताया गया। चेयरमैन साहब बात बड़ी छोटी सी थी। किसी आदमी के नोट खो गये। उन्हें मिलने पर किसी अफसर ने फैसला दे दिया कि तुम्हारी ऐविडैंस काफी नही है इसलिये तुम कोर्ट मे जाओं वह कोर्ट मे चला गया। इस पर सुशमा जी ने इतना समय लगा दिया जिसका कोई हिसाब नही।

श्रीमती सुशमा स्वराजः आन ए पर्सनल एक्सप्लेन ान सर। मैने यह कहा था कि यह रा ि ा तो बहुत थोड़ी थी लेकिन अफसर की लापरवाही है।

श्री सभापतिः मिनिस्टर साहब के बोलने के प चात् आप परसनल एक्सप्लेन ान दे लेना। It is a very ordinary matter. Please take your seat.

श्री मूल चंद जैनः मुझे बहिन सुशमा जी से और चौधरी रिजक राम जी से यह उम्मीद थी कि वे प्वायंट पर जोर देंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे और हाउस की तसल्ली भी करायेंगे कि यह 36 करोड़ के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस किस तरीके से पे ा किये गये और सन् 1978–79 के बजट मे क्यों नही इनको भाामिल किया गया। उस वक्त भी ये चीजें आ सकती थी लेकिन सरकार जानबूझ कर इनको नही लाई होगी। इसमे फाइनैंस डिपार्टमैंट की गलती बतानी चाहिए थी लेकिन उन्होंने इस चीज को बिल्कुल प्वायंट आउट नही किया। उन्होंने एक भी आइटम के बारे मे जिक्र

नही किया कि यह तो बजट के टाईम पर आ सकती थी। इनको यहां बताना चाहिए कि इसमे फाइनैंस डिपार्टमैंट की या फाइनेंस मिनिस्टर साहब की गलती है। अब मैं हाउस के सामने एक एक आइटम के बारे मे बताना चाहता हूं कि किस तरह से खर्च सरकार के सामने आया और सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस के द्वारा हाउस से पता कराना पड़ रहा है।

इस 36 करोड़ मे से 12 करोड़ 59 लाख रूपया तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को और माइनर इरीगे ान ट्यूबवैल कारपोरे ान को कर्जे के तौर पर दिया गया है। बजट के टाईम पर जितना उन्होंने कर्जा मांगा था उतना उस वक्त दिया गया और जो बाद मे जरूरी समझा गया कि जितना पैसा उनको दिया गया था उससे काम नही चल पा रहा है तो यह पैसा दिया गया है।

सात करोड़ 69 लाख रूपये की जो रकम है वह यह है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी है उनका प्रोविडैंट फण्ड जमा होता रहता हे और उस पर इंट्रैस्ट भी मिलता है लेकिन सन् 1966 मे री आर्ग्रेनाईजे ान के टाईम पर स्टाफ की इधर से उधर एलोके ान हुई जिसके कारण उनकी प्रोविडेन्ट फण्ड की कटौती की एडजस्टमैंट नही हो पाई थी। इस कारण से उनका इन्ट्रैस्ट उनके अकाउंट मे जमा नही हो पाया था। इसलिये सन् 1972–73 से 1977–78 तक का जो इंट्रैस्ट जमा नही हो पाया था वह जमा कराया है। यह क्रेडिट डैबिट वाली बात है। यह सिर्फ कागजी कार्यवाही है।

चेयरमैन साहब, पांच करोड़ पचास लाख रूपया सड़कों और पूलों के लिये दिया गया है। क्या हम यह पहले सोच सकते थे कि सन् 1978–79 मे फ्लड आएंगे और हमारा इतना नुक्सान होगा ? क्या पता था कि हमारी सड़कें खराब होगी और पुलो को इतना नुकसान होगा। यह एक प्राकृतिक नुक्सान है। यह पांच करोड़ पचास लाख रूपया सड़कों की मुरम्मत के लिये रखा गया है। इसी तरीके से अढ़ाई करोड़ रूपया ि ाक्षा विभाग को दिया गया है इसमे से 43 लाख रूपया वह हे जो प्राइवेट कालेजिज को दिया गया है। बहिन सुशमा जी ने भी यह माना है कि यह जायज है। जैसा कि सभी साथियों को मालूम है कि गैर सरकारी कालेजों की पोजी ान बहुत ही खराब है उनको संभालने के लिये सरकार इस ओर वि ोश ध्यान दे रही है। हमारी सरकार ने एक सर्वे कमेटी बनाई हुई है और उसे कहा गया है कि जिन प्राइवेट कालेजो की हालत बहुत ही खराब है उन्हे वह अपने अंडर ले। उन बीमार कालेजिज के बारे मे विचार किया गया और गवर्नमैंट उन कालेजिज को ग्रांट देने जा रही है। उन कालेजिज 75 परसैंट कर दी गई है। यह ग्रांट बढ़ा देने से 44 लाख रूपये का खर्चा बढ़ा है। इस खर्चे की बजट के टाईम पर उम्मीद नही की जा सकती थी। 11 लाख रूपये का खर्चा कागजों की कीमत बढ़ जाने से भी बढ़ा है । इसी प्रकार से कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी को चालीस लाख रूपया दिया गया है। उनकी कुछ जरूरियात तो बजट के टाईम पर पूरी कर दी गई थी, फिर कुछ उनकी मांग आई और चालीस लाख रूपया दिया गया।

जैसा कि बहिन सुशमा जी ने माना है कि डेढ़ करोड़ रूपया सरकारी कर्मचारियों को डियरनैस अलाउंस के नाम से दिया गया है। इस डेढ़ करोड़ मे 76 लाख रूपया एजूके ान डिपार्टमैंट को भी दिया गया है। यह कैसे कह सकते है कि यह अढ़ाई करोड़ रूपया जायज नही है और बजट बनाते समय इसके बारे मे पहले ही सोचा जा सकता था।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। पिछले बजट सै ान मे तो इससे कम सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस थे लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उस टाईम पर कहा थ कि ये बहुत ज्यादा सप्लीमैंटरी है इतने नही आने चाहिए। (विघ्न)

श्री सभापतिः यह प्वायंट आफ आर्डर नही है। आप बैठिये।

श्री मूल चंद जैनः चेयरमैन साहब, इसके दो करोड़ 6 लाख रूपया वह हे जो गन्ना उगाने वाले भाईयों को दिया गया है। यह एक तरह से सबसिडी के रूप मे दिया गया है। गन्ने के भाव बहुत कम हो गये थे। इसलिये गन्ने का भाव ठीक दिलाने के लिये भाूगर मिलों को पैसा दिया गया है ताकि किसानों को सही कीमत मिल सके। अब आप सोचिये कि यह पैसा बजट बनाते समय कैसे लाया जा सकता था ? क्या पता था कि गन्ने का भाव इतना गिरेगा और गुड़ की कीमतें इतनी गिरेंगी ?

चेयरमैन साहब, इसी तरीके से हरिजनों की चौपालों का सवाल है। इन चौपालों को बनाने के बारे मे बजट के टाईग्म पर सवाल नही था। यह प्रोग्राम बाद मे बना तो 95 लाख रूपया हरिजनों की चौपालों के लिये दिया गया। इसी तरह से 3.78 लाख रूपये ग्रामोद्योग के लिये दिया गया है। 15—3—1979 को हमारे एम.एल.ए. और मिनिस्टर स्टेट के हरि हिस्से मे जायेंगे और देहाती भाईयो की बेरोजगारी दूर करने के लिये गांवो मे कुछ उद्योग आदि लगवायेंगे।

पिछले दिनों पंचायत के चुनाव हुए थे। सरकार ने यह फैसला किया कि जिन गांवों मे पंचायत सर्वसम्मति से चुनी जायेगी उनको पांच हजार रूप्या ग्रांट के रूप मे दिया जायेगा और यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी स्टेट मे काफी पंचायते सर्वसम्मपि से चुनी गई। इस तरह से उनका 54 लाख 90 हजार रूपया बनता है। इस मांग को बजट बनाने के टाईम पर कैसे लाया जा सकता था ? इस लिये वह 54 लाख 8 हजार रूपया इस मांग मे भाामिल है जोकि इस हाउस से मैं मांग रहा हूं।

श्री सभापतिः अब आप वाइंड अप कीजिये। (विघ्न)

श्री मूल चंद जैनः मैं एक दो मिनट और लूंगा। बस जल्द ही खत्म कर रहा हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन साहब, इनकी तो सोच ही इतनी हैं यह आगे की बात तो सोच ही नही सकते।

श्री वीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जो चौधरी जगजीत सिंह पोहलू की सोच हो सकती है, वह हरेक की सोच नही हो सकती। (विघ्न)

Mr. Chairman: Mr. Pohloo, please take your seat.

श्री मूल चंद जैनः इसी तरीक से 30 लाख रूपया इसमे और रख गया है यह देहातो मे जो फाकल प्वायंटस है, उनके लिये है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सारी की सारी डिमांडज ऐसी है जिनके बारे मे यह नही कहा जा सकता कि इनके बारे मे बजट 1978–79 के मौके पर सोचा जा सकता था। यह सारी की सारी ऐसी डिमांडज है जिनके बारे मे हम उस समय सोच नही सकते थे। यह रा ि ा हमारे हरियाणा के देहातों के विकास के लिये है, खेती के विकास के लिये और जो बाढ़ से पीड़ित हमारे भाई है, उनकी मदद के लिये है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि हाउस इन सारी की सारी डिमांडज को पास कर दे। हां, एक बात और कह कर मैं खत्म करूंगा कि लगभग 36 करोड़ रूपये के लिये जो ये डिमांडज रखी गई है इनमे से 22 करोड़ 10 लाख रूपये के करीब तो भारत सरकार की जो स्कीमें है, उनसे मजीद मदद है। भोश जो 13 करोड़ 85 लाख रूपया है, यह हमारे दूसरे महकमों के खर्चो मे से बचत करके हम इसे खर्च कर रहे है। चौधरी रिजक राम जी ने यह जो प्वायंट उठाया था कि साहब बचत तो हम कर ही नही रहे है, उसके जवाब मे मैं उन्हे यह बताना चाहता हूं कि हम इतना सारा पेसा बचत करके ही

खर्च कर रहे है। इसलिये इस पैसे के लिये टैक्स लगाने की कोई बात नही है। अंत मे मेरी प्रार्थना यह है कि हाउस इन सप्लीमैंटरी डिमांडज को पास कर दे।

श्रीमती सुशमा स्वराजः आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेने ान, सर (व्यवधान व भाोर) आपने कहा था कि मंत्री महोदय के बाद समय दूंगा।

श्री लछमन सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मंत्री महोदय के जवाब के बाद कोई मैंबर नही बोल सकता।

श्रीमती सुशमा स्वराजः आपने स्वयं तो रूलिंग दी थी कि आप उनके बाद बोल लेना। (व्यवधान)

Mr. Chairman: Please take your seat now.

श्रीमती सुशमा स्वराजः चेयरमेन साहब, आप अपनी रूलिंग को खद ही कन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। पहले तो आपने यह कहा कि मंत्री महोदय के जवाब देने के बाद बोल लेना और अब आप मुझे बोलने के लिये समय नही दे रहे है ?

Mr. Chairman: I will let you know why I am over ruling it. Please take your seat.

श्रीमती सुशमा स्वराजः मैं तो सिर्फ एक पर्सनल बात जो की गयी, उसका स्पश्टीकरण देना चाहती हूं। पहले तो आपने खुद कहा कि जवाब दे देना लेकिन अब आप समय नही दे रहे

हो। तो आप अपनी रूलिंग को खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हो। (व्यवधान)

Mr. Chairman: The time is over. Now I will apply quillotine. (Interruptions) As there is no time now, I over rule my previous ruling.

Now I will put the various demands to the vote of the House.

Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 652350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1097760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4976515 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4026550 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 4-Revenue.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7293700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 7-Other Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 53023000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 8-Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25015400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11642855 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 522814 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2749815 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4829420 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20250680 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17977930 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 21-Community Development.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 125893100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 2 p.m. on Friday, the 16th March, 1979.

(The Sabha then *adjourned till 2 p.m. on Friday, the 16th March, 1979)